UPSC-CSE 2027/28

DAILY CURRENT AFFAIRS

ONE STOP SOLUTION

By **Faiyaz Sir**



The Indian EXPRESS

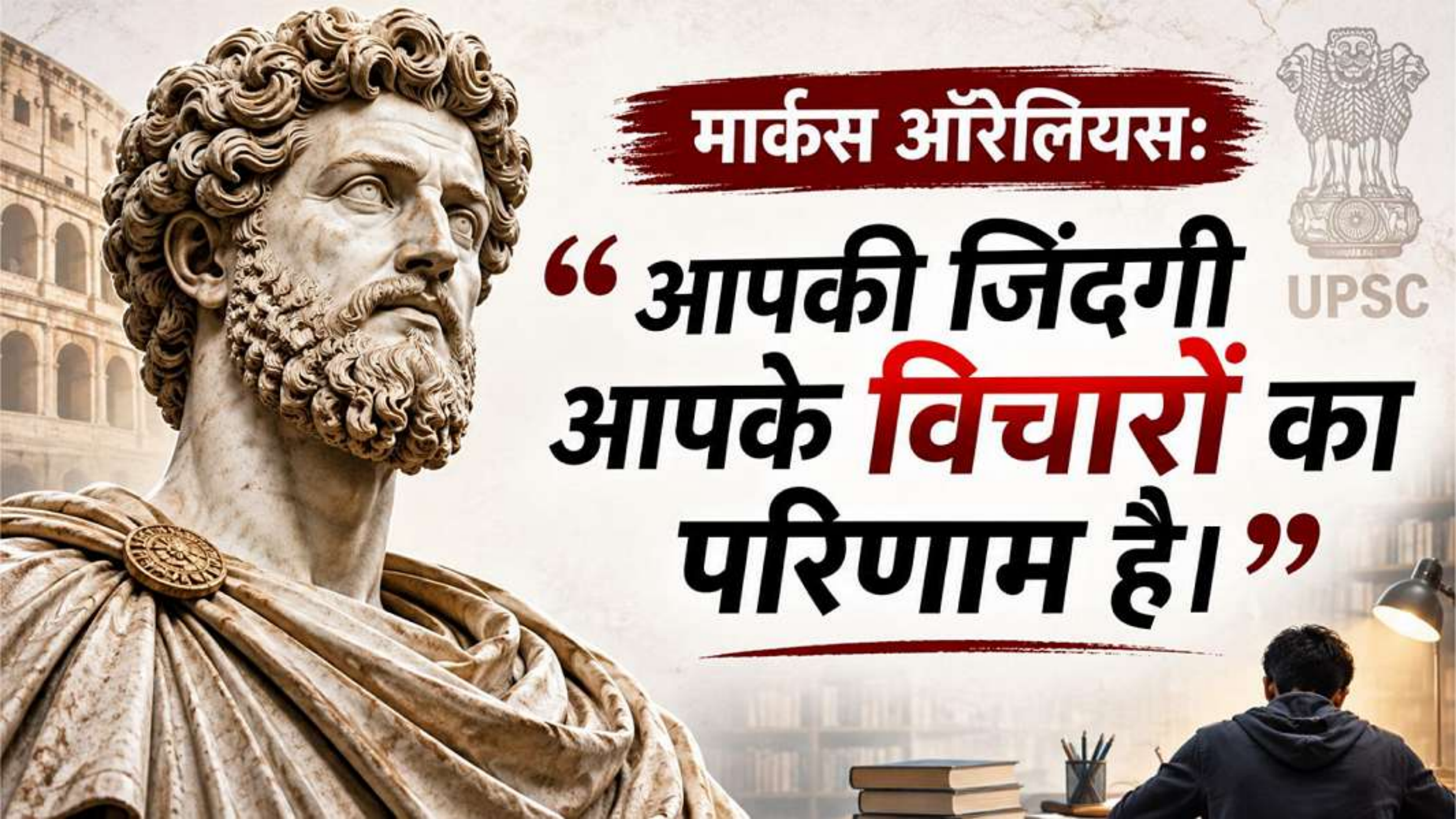
THE HINDU

pib PRESS INFORMATION BUREAU

13 NOVEMBER

COMPLETE COVERAGE | EXAM FOCUSED | ANALYSIS MADE EASY | STATIC + CURRENT INTEGRATION

STAY AHEAD STAY PREPARED


मार्कस ऑरेलियस:
“ आपकी जिंदगी आपके विचारों का परिणाम है। ”
UPSC

आज क्या पढ़ेंगे?

- एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड
- Siang Project
- Ladakh
- Diwali & Pollution
- CPI
- Arunachal Pradesh – 26 Road
- Removal of IAS
- WHO Report – Global Tuberculosis
- Public Transport and Bacteria Transmission
- Cop-31 – UNFCCC
- Earth shot Price
- 31st CII partnership Summit
- Oil Import – Russia
- NVIDIA CEO resign
- 5th India Bangladesh
- Consular Dialogue
- Ukraine-Russia Peace Talk
- China-Taiwan Conflict
- Saudi Arab East-West Pipeline
- भारत कृषि सम्मेलन 2026
- राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव 2026
- 57वां इफ्फी

Rural Prosperity

एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड

प्रविष्टि तिथि: 12 NOV 2026 11:45 AM

सभी लोगों तक खाद्य सुरक्षा

उठाने योग्य से लेकर समावेशन तक: खाद्यान्न तक पहुंच में परिवर्तन

वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा वर्ष 2019 में शुरू की गई थी। यह **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)** में एक प्रमुख सुधार है, जिसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के अंतर्गत आने वाले राशन कार्डों और लाभार्थियों के लिए पूरे देश में पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। **एनएफएसए सब्सिडी वाले खाद्यान्न के लिए कानूनी पात्रता सुनिश्चित करता है, जबकि टीपीडीएस पात्र लाभार्थियों को इन खाद्यान्नों का वितरण करता है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस)** में किए गए सुधारों के तहत ओएनओआरसी तकनीक का उपयोग करके लाभार्थियों को देश में कहीं भी अपने हक के खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। इस पहल ने प्रवासी आबादी के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत किया है तथा अधिक एकीकृत, समावेशी और लाभार्थी-केंद्रित कल्याणकारी सेवाओं के वितरण की दिशा में प्रगति की है।

- देशभर में किसी भी उचित दर की दुकान से नया राशन कार्ड बनवाए बिना खाद्यान्न की पात्रता प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। खाद्यान्न की पात्रता को राज्यों के बीच उठाने योग्य बनाता है।
- प्रवासी श्रमिकों और परिवारों को निवास स्थान बदलने के बाद भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ प्राप्त करने में सहायता करता है।
- लाभार्थी जहां भी निवास करते हैं, वहां उन्हें सब्सिडी वाले खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।
- देशभर में एनएफएसए लाभार्थियों के लिए पीडीएस तक पहुंच को मजबूत करता है।

पोर्टेबिलिटी की प्रमुख उपलब्धियां

- ओएनओआरसी ने खाद्यान्न तक पहुंच को सुगम, पोर्टेबल और देशव्यापी बनाकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में परिवर्तनकारी सुधार किया है।
- ओएनओआरसी को सभी 36 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है, जिससे पीएमजीकेएवाई के **100 प्रतिशत लाभार्थी** इसके दायरे में आ गए हैं।
- ओएनओआरसी के माध्यम से हर महीने लगभग **3.27 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन** किए जाते हैं।
- अपनी शुरुआत से अब तक, इसके तहत **233 करोड़ से अधिक अंतर-राज्यीय और राज्य के भीतर पोर्टेबिलिटी लेनदेन** दर्ज किए गए हैं, जिसके माध्यम से **614 एलएमटी से अधिक खाद्यान्न** वितरित किया गया है।



सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पारदर्शिता और वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाना

- सरकार ने राशन की पोर्टेबिलिटी के साथ डिजिटल प्रमाणीकरण, डेटा-आधारित लक्षित लाभ वितरण और प्रौद्योगिकी-सक्षम वितरण व्यवस्था को भी बढ़ावा दिया है, ताकि पारदर्शिता और अंतिम छोर तक वितरण में सुधार किया जा सके।
- **100 प्रतिशत डिजिटलीकरण:** अक्टूबर 2026 तक सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड और लाभार्थी डेटाबेस का **100 प्रतिशत डिजिटलीकरण** किया जा चुका है। इसके तहत लगभग **78.65 करोड़** लाभार्थी शामिल हैं और यह डेटा राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के सार्वजनिक पारदर्शिता पोर्टलों पर उपलब्ध है। केन्द्रीय प्रणाली में दर्ज **20.51 करोड़ राशन कार्डों** में से **98.8 प्रतिशत (20.27 करोड़)** राशन कार्ड **आधार से जोड़े जा चुके हैं**। आधार से जुड़े लाभार्थियों की कुल संख्या **76.97 करोड़** है। 30 सितंबर 2026 तक **71.52 करोड़** का ई-केवाईसी किया जा चुका है, जो कुल लाभार्थियों का **91 प्रतिशत है।**

- **पारदर्शी शिकायत निवारण:** सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में पारदर्शिता पोर्टल, ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली और टोल-फ्री हेल्पलाइन संचालित हैं।
- **कम्प्यूटरीकृत आपूर्ति श्रृंखला:** देशभर में खाद्यान्न का ऑनलाइन आवंटन लागू किया गया है, जबकि **31 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों** में आपूर्ति श्रृंखलाओं को कम्प्यूटरीकृत किया गया है।
- **ई-पीओएस सक्षम उचित दर की दुकानें :** कुल **5.51 लाख उचित दर की दुकानों में से 99.8 प्रतिशत (5.50 लाख) दुकानें ई-पीओएस उपकरणों** के साथ संचालित हैं।
- **उचित लक्ष्यीकरण एवं डुप्लीकेट रिकॉर्ड हटाना:** उन्नत आधार और पीडीएस डेटा विश्लेषण के माध्यम से **5.95 करोड़** संदिग्ध रिकॉर्ड चिन्हित किए गए, जिसके परिणामस्वरूप **2.58 करोड़** डुप्लीकेट या अपात्र प्रविष्टियां हटाई गईं। राइटफुल टार्गेटिंग संस्करण 3.63 के तहत 68 लाख रिकॉर्ड चिन्हित किए गए और हटाए गए।
- **निर्मल एवं सक्षम: सार्वजनिक वितरण प्रणाली में स्वचालन के साथ राशन परिवहन एवं हैंडलिंग-आय सहायता योजना (सार्थक-पीडीएस)** की व्यापक योजना के अंतर्गत ये पहलें डेटा आर्किटेक्चर/विश्लेषण (निर्मल) तथा खरीद से लेकर वितरण तक रियल-टाइम डेटा एकीकरण, जिसमें वाहन लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम (सक्षम) भी शामिल है, को मजबूत करती हैं। **सार्थक-पीडीएस** अंतर-राज्यीय नहीं, बल्कि राज्य के भीतर खाद्यान्न की आवाजाही, हैंडलिंग और उचित मूल्य दुकान डीलरों के मार्जिन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। साथ ही, यह एकीकृत, नागरिक-केन्द्रित और इंटरऑपरेबल पीडीएस आर्किटेक्चर तैयार करता है। इस योजना का उद्देश्य 31 मार्च 2031 तक एनएफएसए के तहत अंतिम छोर तक खाद्यान्न की डिलीवरी सुनिश्चित करना, लीकेज को न्यूनतम करना और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना है।
- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार योजना (स्मार्ट-पीडीएस): सार्थक-पीडीएस** के अंतर्गत **स्मार्ट-पीडीएस** राशन कार्ड, वितरण, आपूर्ति श्रृंखला और शिकायत निवारण को डिजिटल रूप से एकीकृत करता है। साथ ही, एकीकृत केन्द्रीय प्रणाली के माध्यम से राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के स्तर पर प्रौद्योगिकी संबंधी कमियों को दूर करता है।

मेरा राशन ऐप: खाद्यान्न की आपकी उंगलियों तक पहुंच

- ओएनओआरसी के तहत प्रौद्योगिकी-आधारित टीपीडीएस सुधारों के एक भाग के रूप में, विभाग ने **मेरा राशन** मोबाइल एप्लिकेशन शुरू किया। **13 भाषाओं** में उपलब्ध यह ऐप लाभार्थियों को राशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है।
- **प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:**
- मासिक खाद्यान्न पात्रता का विवरण देखना
- पिछले लेनदेन का विवरण देखना
- आधार-सीडिंग की स्थिति की पुष्टि करना
- राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के लिए पात्रता की जांच करना
- ओएनओआरसी के लिए स्वेच्छा से पंजीकरण
- जीपीएस का उपयोग करके आसपास की उचित दर की दुकानों का पता लगाना
- मानचित्र के माध्यम से निकटतम एफपीएस तक पहुंचने का मार्ग देखना
- मेरा राशन ऐप लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासियों, को आसपास की एफपीएस का पता लगाने और नए क्षेत्र में अपनी खाद्यान्न पात्रता प्राप्त करने में सहायता करता है।

- मेरा राशन ऐप लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासियों, को आसपास की एफपीएस का पता लगाने और नए क्षेत्र में अपनी खाद्यान्न पात्रता प्राप्त करने में सहायता करता है।

समावेशी और गरिमापूर्ण खाद्य सुरक्षा की ओर

- ओएनओआरसी ने खाद्यान्न तक पहुंच को पोर्टेबल, देशव्यापी और प्रौद्योगिकी-सक्षम बनाकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बदलाव किया है। सभी 36 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में इसके कार्यान्वयन के साथ-साथ बड़ी संख्या में पोर्टेबिलिटी लेनदेन इसके माध्यम से खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने में इसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाते हैं। डिजिटलीकृत लाभार्थी डेटाबेस, ई-पीओएस से सक्षम उचित मूल्य की दुकानों, सार्थक-पीडीएस ढांचे और मेरा राशन ऐप के माध्यम से यह प्रणाली अधिक पारदर्शी, एकीकृत और लाभार्थी-केन्द्रित बन रही है।
- सामूहिक रूप से, ये सुधार अंतिम छोर तक वितरण व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि लाभार्थियों को वे जहां भी रहते और काम करते हैं, वहां खाद्य सुरक्षा उपलब्ध हो।

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न (Prelims Practice Question)

प्रश्न: 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' (ONORC) योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस योजना की शुरुआत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा वर्ष 2019 में की गई थी।
2. यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को देश में कहीं भी किसी भी उचित दर की दुकान से अपना सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है।
3. इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए देश के भीतर प्रवास करने पर नया राशन कार्ड बनवाना अनिवार्य है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (Mains Practice Question)

- **प्रश्न:** 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' (ONORC) योजना ने भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की कार्यप्रणाली को किस प्रकार रूपांतरित किया है? प्रवासी आबादी की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में इस पहल की प्रमुख सफलताओं और चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। *(उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)*

Why is the Siang project contentious?

The proposed Siang Upper Multipurpose Project in Arunachal Pradesh has triggered protests by the Adi community, which says at least 40 villages would be affected, 27 of them submerged; the government, however, says the project will store and regulate water, reduce flood risks and generate employment for the youth

EXPLAINER

Jacob Koshy

The story so far

The proposed Siang Upper Multipurpose Project (SUMP) in Arunachal Pradesh has triggered protests by the Adi community, and activists have been arrested or detained since October. Protesting groups have rejected the State government's offer to hold talks on November 5.

What is the SUMP project?

It is a proposed dam on the Siang – as the Brahmaputra is known in Arunachal Pradesh – to be built by the National Hydroelectric Power Corporation (NHPC).

First declared a national project in 2008, its estimated power capacity is between 11,000 and 11,200 MW. The Deputy Chief Minister, Chowna Mein of the BJP, has cited a dam height of 280 to 300 metres and about 9.2 billion cubic metres of live storage, which refers to the usable water in a dam that can actually be released, excluding the unusable bottom layer.

However, India has an established process for approving such projects. Clearing such large dams involves multiple steps, such as forest and environmental clearance from the State as well as Central Government-constituted expert appraisal committees.

What stage is the project at?

So far, the project is only at the stage of a Pre-Feasibility Report (PFR), being prepared by NHPC, which is an early study of whether the project can be built safely.

They also require a full impact study with a year of baseline data, a dam-break analysis and a disaster management plan. Pareng, Dite Dime and Uggeng are among the sites identified for it.



Raising their voices: The Adi community protests against the dam, in Yingkiong village in Upper Siang district of Arunachal Pradesh. PTI/ TAI NOWAM

What does it promise?

The Government says it will store and regulate water, cut flood risk in Arunachal Pradesh and Assam, create jobs for the youth, and strengthen water and energy security. Mr. Mein has said power is a "secondary" benefit from the dam.

Why are people protesting?

Adi villagers say that at least 40 villages would be affected, of which 27 would be submerged. They say this would destroy paddy fields and orange orchards, as well as ancestral burial grounds and river-linked religious practices. There are also objections to the way authorities are gathering consent. Villagers allege that signatures on Memoranda of Understanding for the PFR were obtained through deceit, pressure and threats to withhold welfare benefits. *The Hindu* reported that a copy of the MoU it reviewed describes the consent as being for the PFR study alone and not for the dam.

Tensions have nevertheless escalated, with elderly protesters allegedly being lathi-charged on October 4, injuring 54. Activists were arrested under the State's unlawful activities law on October 9. A march in Pasighat, a major town and the headquarters of the East Siang district, on October 23, turned violent, and NHPC premises were set on fire.

What is the government's rationale?

Rejecting talks, one youth leader, quoted by *The Hindu*, said that discussions cannot happen "while they are pointing guns at us." The Adi have also proposed damming smaller tributaries instead.

China's planned Medog dam upstream, reported at 60,000 MW, is cited as the main driver. Mr. Mein says that the Medog dam is built for power generation, with about 5.5 billion cubic metres of storage. SUMP's larger storage capacity, he argues, could cushion sudden upstream releases. Some villagers ask why they should bear the cost of the Centre's failure to secure a water treaty with China.

What is the backdrop of hydropower in Arunachal Pradesh?

The State has long been seen as India's hydropower frontier. *The Hindu* reports that a veteran politician says the State signed 143 hydropower agreements in the late 2000s, opening up its rivers, and most never took off. An earlier environmental assessment brief for a 3,750 MW "Stage-II" Siang Upper project shows that the idea has existed in other forms for years.

Have States weaponised water?

Yes, though rarely as a standalone cause of war. A 2025 Geneva Graduate Institute study notes that water has long been used in conflict, for instance by flooding through destroyed dams, and that some scholars say upstream states manipulate flows to pressure downstream neighbours.

Ethiopia's Grand Ethiopian Renaissance Dam on the Blue Nile, formally inaugurated in 2025, has been contested by downstream Egypt and Sudan for over a decade. The two countries have sought binding rules on how the reservoir is filled and operated, though no agreement has been reached.

At home, the Indus Waters Treaty (1960) gave India the eastern rivers and Pakistan the western ones. After the April 2025 Pahalgam attack, India placed it "in abeyance". A Court of Arbitration ruled unanimously on August 31, 2026, that the treaty remains in force and abeyance is unauthorised. However India has stated that it does not recognise that court.

THE GIST

- The SUMP is a proposed dam on the Siang — as the Brahmaputra is known in Arunachal Pradesh — to be built by the National Hydroelectric Power Corporation (NHPC)
- The Deputy Chief Minister, Chowna Mein of the BJP, says the SUMP's large storage capacity could cushion sudden upstream releases from the Medog dam planned by China

सियांग परियोजना विवादित क्यों है?

- अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित 'सियांग अपर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट' (SUMP) के खिलाफ आदि समुदाय (Adi community) ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। समुदाय का कहना है कि इससे कम से कम 40 गाँव प्रभावित होंगे और उनमें से 27 पूरी तरह जलमग्न हो जाएंगे। वहीं, सरकार का कहना है कि यह परियोजना पानी को संचित और विनियमित करेगी, बाढ़ के जोखिम को कम करेगी और युवाओं के लिए रोजगार पैदा करेगी।



अब तक की कहानी (The story so far):

- अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित **सियांग अपर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट (SUMP)** के कारण आदि समुदाय द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और अक्टूबर से कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है।
- विरोध प्रदर्शन करने वाले समूहों ने 5 नवंबर को बातचीत के राज्य सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है।

SUMP परियोजना क्या है?

- यह सियांग नदी (जिसे अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है) पर एक प्रस्तावित बांध है, जिसे नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (NHPC) द्वारा बनाया जाना है।
- इसे पहली बार 2008 में एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था, इसकी अनुमानित बिजली उत्पादन क्षमता 11,000 और 11,200 मेगावाट के बीच है। भाजपा के उपमुख्यमंत्री चौना मीन ने 280 से 300 मीटर ऊंचे बांध और लगभग 9.2 अरब क्यूबिक मीटर लाइव स्टोरेज का हवाला दिया है, जो उस पानी को संदर्भित करता है जिसे वास्तव में छोड़ा जा सकता है (अनुपयोगी निचली परत को छोड़कर)।
- हालांकि, भारत में ऐसी परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए एक स्थापित प्रक्रिया है। इतने बड़े जंगलों को साफ करने में कई चरण शामिल हैं, जैसे कि राज्य से वन और पर्यावरण मंजूरी के साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियां।

परियोजना किस चरण में है?

- अब तक, यह परियोजना केवल **प्री-फेसिबिलिटी रिपोर्ट (PFR)** के चरण में है, जिसे NHPC द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो इस बात का प्रारंभिक अध्ययन है कि परियोजना को सुरक्षित रूप से बनाया जा सकता है या नहीं।
- इसके अलावा डेटा के एक साल के बेसलाइन डेटा, बांध-टूटने के विश्लेषण (dam-break analysis) और आपदा प्रबंधन योजना के साथ एक पूर्ण प्रभाव अध्ययन की भी आवश्यकता होती है। पारोंग, दित्ते दिमे और उग्गेन्ग इसके लिए पहचाने गए स्थलों में से हैं।

यह क्या वादा करती है?

- सरकार का कहना है कि यह पानी को संचित और विनियमित करेगी, अरुणाचल प्रदेश और असम में बाढ़ के जोखिम को कम करेगी, युवाओं के लिए नौकरियां पैदा करेगी, और जल तथा ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी। श्री मीन ने कहा है कि बिजली बांध से मिलने वाला "दूसरा" लाभ है।

लोग विरोध क्यों कर रहे हैं?

- आदि ग्रामीणों का कहना है कि कम से कम 40 गाँव प्रभावित होंगे, जिनमें से 27 जलमग्न हो जाएंगे। उनका कहना है कि इससे धान के खेत और संतरे के बागों के साथ-साथ पुश्तैनी दफन भूमि और नदी से जुड़ी धार्मिक प्रथाएं नष्ट हो जाएंगी। अधिकारियों द्वारा सहमति प्राप्त करने के तरीके पर भी आपत्तियां हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि धोखे, दबाव और कल्याणकारी लाभ रोकने की धमकी देकर PFR के लिए सहमति ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर प्राप्त किए गए थे। द *हिंदू* की एक रिपोर्ट में समीक्षा किए गए दस्तावेजों में बताया गया है कि सहमति केवल PFR अध्ययन के लिए थी, बांध के लिए नहीं।
- इसके बावजूद तनाव बढ़ गया है, 4 अक्टूबर को बुजुर्ग प्रदर्शनकारियों पर कथित रूप से लाठीचार्ज किया गया, जिससे 54 लोग घायल हो गए। 9 अक्टूबर को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। 23 अक्टूबर को पूर्वी सियांग जिले के मुख्यालय पासीघाट में एक प्रमुख शहर और एनएचपीसी परिसर में एक मार्च हिंसक हो गया और आग लगा दी गई।

सरकार का तर्क क्या है?

- बातचीत को खारिज करते हुए, द *हिंदू* द्वारा उद्धृत एक युवा नेता ने कहा, "जब वे हमारी ओर बंदूकें ताने हुए हैं तब चर्चा नहीं हो सकती।" आदि लोगों ने इसके बजाय अन्य छोटी सहायक नदियों पर बांध बनाने का प्रस्ताव रखा है।
- चीन के प्रस्तावित मेदोर्ग बांध (Medog dam) को ऊपर की तरफ 60,000 मेगावाट पर रिपोर्ट किया गया है, जो मुख्य चालक के रूप में उद्धृत है। श्री मीन का कहना है कि मेदोर्ग बांध बिजली उत्पादन के लिए बनाया गया है, जिसमें लगभग 5.5 अरब क्यूबिक मीटर स्टोरेज है। SUMP की बड़ी भंडारण क्षमता, ऊपर की ओर से अचानक छोड़े जाने वाले पानी को कुशन (कम) कर सकती है। कुछ ग्रामीणों का पूछना है कि चीन के साथ जल संधि सुरक्षित करने में केंद्र की विफलता की कीमत उन्हें क्यों चुकानी चाहिए।

अरुणाचल प्रदेश में जलविद्युत की पृष्ठभूमि क्या है?

- इस राज्य को लंबे समय से भारत की जलविद्युत सीमा (hydropower frontier) के रूप में देखा जाता रहा है। द *हिंदू* की रिपोर्ट है कि एक दिग्गज राजनेता ने 2000 के दशक के अंत में 143 जलविद्युत समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिससे इसकी नदियाँ खुलीं, और अधिकांश कभी जमीन पर नहीं उतरीं। 3,750 मेगावाट "स्टेज-II" सियांग ऊपरी परियोजना के लिए एक पहले का पर्यावरण मूल्यांकन संक्षिप्त विवरण दिखाता है कि यह विचार वर्षों से अन्य रूपों में मौजूद रहा है।

क्या राज्यों ने पानी को हथियार बना लिया है?

- हाँ, हालांकि युद्ध के एक स्टैंडअलोन कारण के रूप में यह शायद ही कभी होता है। 2025 के जिनेवा ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के अध्ययन में उल्लेख किया गया है कि पानी लंबे समय से संघर्ष में रहा है, उदाहरण के लिए क्षतिग्रस्त बांधों के माध्यम से बाढ़ लाकर, और कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि ऊपरी धारा के राज्य निचले धारा के पड़ोसियों पर दबाव बनाने के लिए जल प्रवाह में हेरफेर करते हैं।
- नील नदी पर ग्रैंड इथोपियन रेनेसां डैम, जिसका औपचारिक उद्घाटन 2025 में हुआ था, पर निचले हिस्से के मिस्र और सूडान द्वारा लंबे समय से विवाद किया जाता रहा है। दोनों देश इस बात पर बाध्यकारी नियम चाहते हैं कि जलाशय को कैसे भरा और संचालित किया जाए, हालांकि कोई समझौता नहीं हो पाया है।
- घर में, सिंधु जल संधि (1960) ने भारत को पूर्वी नदियाँ और पाकिस्तान को पश्चिमी नदियाँ दीं। अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले के बाद, भारत ने इसे "निलंबन" में डाल दिया। 31 अगस्त, 2026 को सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए एक मध्यस्थता न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संधि लागू है और निलंबन अनधिकृत है। हालांकि भारत ने कहा है कि वह उस अदालत को मान्यता नहीं देता है।

मुख्य सार (THE GIST)

- SUMP सियांग नदी पर एक प्रस्तावित बांध है — जिसे अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र के रूप में जाना जाता है — जिसे नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक Power Corporation (NHPC) द्वारा बनाया जाना है।
- भाजपा के उपमुख्यमंत्री चौना मीन का कहना है कि SUMP की बड़ी भंडारण क्षमता चीन द्वारा योजनाबद्ध मेदोर्ग बांध से ऊपर की ओर से अचानक छोड़े जाने वाले पानी को कुशन (कम) कर सकती है।

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न (Prelims Practice Question)

प्रश्न: 'सियांग अपर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट' (SUMP) और उससे संबंधित भौगोलिक व रणनीतिक पहलुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह परियोजना सियांग नदी पर प्रस्तावित है, जिसे अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है।
2. इस परियोजना का निर्माण नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (NHPC) द्वारा किया जाना है।
3. इसका मुख्य उद्देश्य केवल बिजली उत्पादन करना है और इसमें बाढ़ नियंत्रण या जल भंडारण की कोई क्षमता नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (Mains Practice Question)

- **प्रश्न:** "अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार नदियों पर बड़े बांधों का निर्माण रणनीतिक जल सुरक्षा और स्थानीय पारिस्थितिक व सामाजिक चिंताओं के बीच एक जटिल द्वंद्व उत्पन्न करता है।" अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित 'सियांग अपर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट' (SUMP) के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। *(उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)*

Why did Ladakh groups decry the announcement of polls?

Why did LAB and KDA seek the postponement of polls? What led to the impasse in talks with the Centre?

Peerzada Ashiq

The story so far:

The Lieutenant Governor-led administration of Ladakh has announced back-to-back elections in the Union Territory (U.T.). The three-tier polls – hill councils, panchayat and municipal elections – will be held in the next one month. While the panchayat and municipal elections are slated for November 21, the hill council elections will be held on December 4.

Ladakh is a U.T. without a legislature. So, these polls are key to provide platforms to public representatives in the region. However, the short window provided by the State Election Commission (SEC) is likely to make it hard for political parties to chart the course for their campaigning and enter into possible alliances.

How are these elections different?

Previously, Ladakh operated with only two hill development councils – the Ladakh Autonomous Hill Development Council (LAHDC) in Leh and LAHDC in Kargil – which together covered 52 constituencies, split evenly with 26 in each district. However, the Ladakh administration restructured the region's local governance by creating six new districts and establishing dedicated hill councils for each of them.

As a result of this administrative expansion, the upcoming local elections will be held across 100 constituencies. Each new district council will now comprise between seven and 24 elected members, down from the previous 26. In a first, 36 of the 100 total LAHDC seats have been reserved for women.

Meanwhile, Chief Secretary Ashish Kundra assured that the newly formed hill councils "would retain all powers vested in them under the existing law."

What makes polls difficult in Ladakh?

Conducting elections in Ladakh comes with logistical and geographical challenges. The region, spread across 59,146 square kilometres, has a sparse population of just 2.74 lakh, according to the 2011 census.

The region has 1.90 voters, according to the Election Commission of India (ECI) figures of 2025. So, the 100 constituencies going to voting will have an average 1900 voters per constituency.

Several villages are located at altitudes as high as 15,000 feet above the sea level and there are many passes, connecting the valleys and higher reaches, which get closed due to snowfall in winters. To overcome these conditions, the Ladakh administration has promised to provide heating and specialised logistical support to facilitate the polling.

According to Mr. Kundra, a portion of local representatives has already been decided without a contest.

Out of 192 *panchayat halqas*, 56 *sarpanches* have already been elected unopposed, leaving polls to be held in only 137 seats. Similarly, 1,186 out of 1,428 *panch* candidates were elected unopposed. While all 21 wards in the Leh Municipal Council will go to the polls, four of the 17 wards in the Kargil Municipal Council have already elected their representatives unopposed.

Meanwhile, the Ladakh Chief Secretary has termed these elections as steps to "strengthening democratic institutions and ensuring their early constitution".

Why have civil society groups questioned the polls?

Ladakh has two key civil society bodies – Leh Apex Body (LAB) and Kargil Democratic Alliance (KDA). These bodies, which are amalgams of socio-political and religious groups, have been negotiating with the Centre over their core demands of Statehood and Sixth Schedule. Now, both the bodies are questioning the timing of these elections.

LAB co-chairperson Tsering Dorjey Lakrook expressed concern over likely poor participation because a sizable population of the region have moved to warmer places, especially students and elderly population. The region was facing "unilateral decisions and order-after-order without consultation," KDA co-chairperson Sajjad Kargilli added. These groups are demanding postponement of hill council elections to April-May next year. Echoing this, Ladakh Member of Parliament (MP) Haji Haneefa urged the Lieutenant Governor and the State Election Commissioner (SEC) "to consider the region's geographical and climatic conditions before scheduling polls" and claimed that elections in winter could deprive many people of their right to vote.

Mr. Lakrook alleged that the Centre was taking negotiating civil society groups "for granted" and stated he suspected the government "was up to some mischief." He also demanded that the government make public the judicial inquiry report into the September 2025 Leh violence and ensure "justice [is] delivered to the victims." Four civilians died and around 80 were injured in alleged security forces firing in September last year.

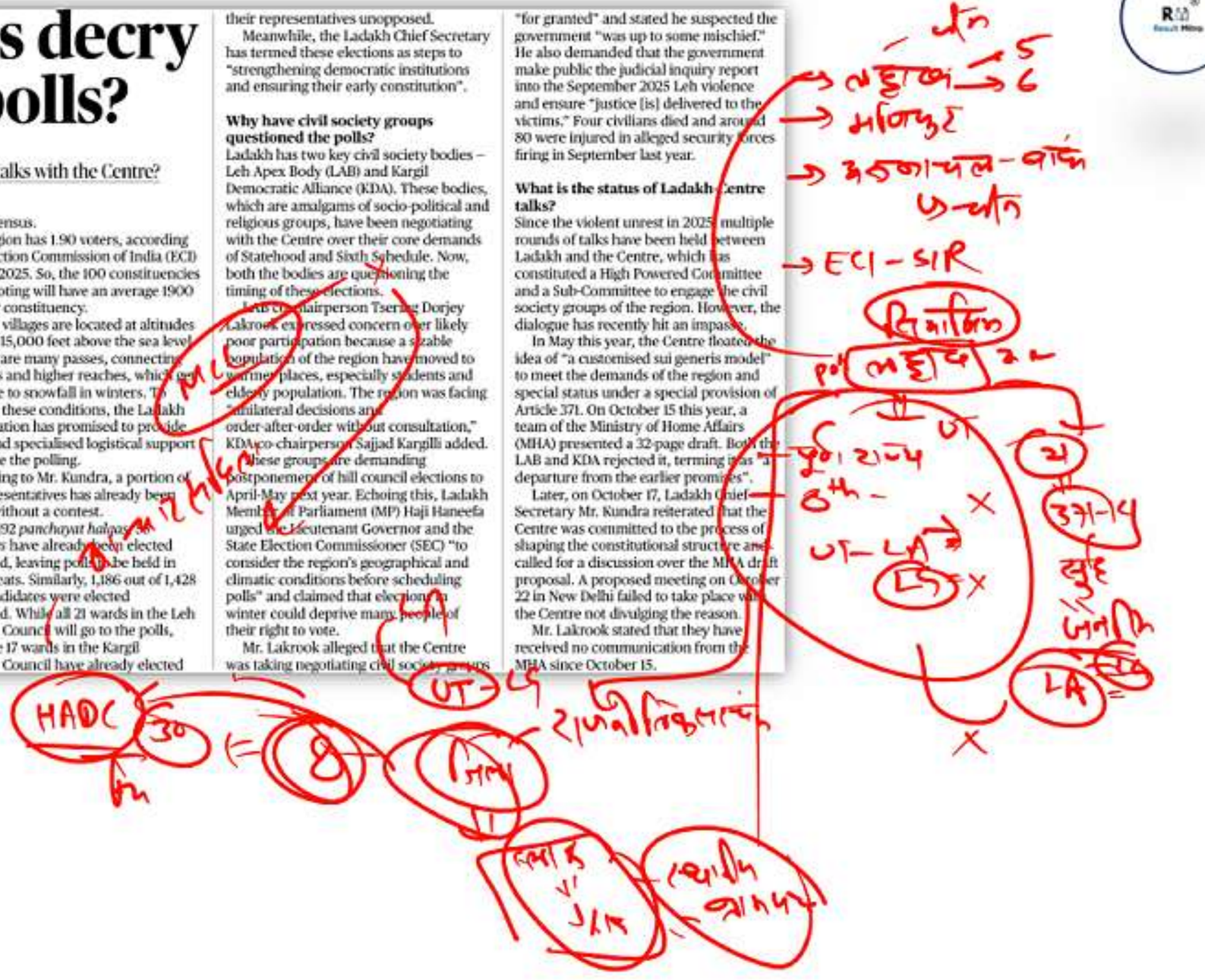
What is the status of Ladakh-Centre talks?

Since the violent unrest in 2025, multiple rounds of talks have been held between Ladakh and the Centre, which has constituted a High Powered Committee and a Sub-Committee to engage the civil society groups of the region. However, the dialogue has recently hit an impasse.

In May this year, the Centre floated the idea of "a customised sui generis model" to meet the demands of the region and special status under a special provision of Article 371. On October 15 this year, a team of the Ministry of Home Affairs (MHA) presented a 32-page draft. Both the LAB and KDA rejected it, terming it as "a departure from the earlier promises".

Later, on October 17, Ladakh Chief Secretary Mr. Kundra reiterated that the Centre was committed to the process of shaping the constitutional structure and called for a discussion over the MHA draft proposal. A proposed meeting on October 22 in New Delhi failed to take place with the Centre not divulging the reason.

Mr. Lakrook stated that they have received no communication from the MHA since October 15.



लद्दाख में चुनावों की घोषणा पर समूहों ने क्यों आपत्ति जताई?

- **मुख्य खबर:** लद्दाख के उपराज्यपाल प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश में त्रि-स्तरीय चुनावों (पहाड़ी परिषद, पंचायत और नगर निकाय चुनावों) की घोषणा कर दी है, जो अगले एक महीने के भीतर होने वाले हैं। पंचायत चुनाव 21 नवंबर को और पहाड़ी परिषद के चुनाव 4 दिसंबर को होंगे।
- **यह चुनाव अलग क्यों हैं:** पहले लद्दाख में केवल दो पहाड़ी परिषदें थीं—लेह और कारगिल की लेह स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC)—जो कुल 52 निर्वाचन क्षेत्रों को कवर करती थीं। प्रशासनिक पुनर्गठन के बाद अब नए जिलों और परिषदों के साथ स्थानीय चुनाव 100 निर्वाचन क्षेत्रों में होंगे। कुल 100 सीटों में से पहली बार 36 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं।
- **लद्दाख के समूहों (LAB और KDA) के सवाल:** लेह अपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की अपनी मुख्य मांगों को लेकर केंद्र से बातचीत कर रहे हैं। इन समूहों ने चुनावों के समय और बिना किसी परामर्श के लिए गए "एकतरफा फैसलों" पर सवाल उठाया है और पहाड़ी परिषद के चुनावों को अगले साल अप्रैल-मई तक टालने की मांग की है।
- **भौगोलिक और मौसमी कठिनाइयाँ:** सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी और ठंड के कारण कई गाँव कट जाते हैं और लोग (विशेषकर छात्र और बुजुर्ग) गर्म इलाकों में चले जाते हैं। ऐसे में सर्दियों में चुनाव कराने से कई लोगों का मतदान का अधिकार छिन सकता है।
- **केंद्र के साथ बातचीत की स्थिति:** 2025 की हिंसक घटनाओं के बाद केंद्र और लद्दाख के बीच कई दौर की बातचीत हुई है और एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। हालांकि, केंद्र द्वारा पेश किए गए एक मसौदे (ड्राफ्ट) को LAB और KDA ने खारिज कर दिया है, जिसके बाद से बातचीत में गतिरोध आ गया है।

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims Practice Question)

प्रश्न: भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान करती है।
2. इस अनुसूची के तहत गठित स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) को कानून बनाने की विधायी, न्यायिक और वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
3. लद्दाख के नागरिक समाज समूह और राजनीतिक संगठन लंबे समय से इस क्षेत्र के लिए संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

मुख्य परीक्षा (Mains Practice Question)

- **प्रश्न:** लद्दाख में हालिया प्रशासनिक पुनर्गठन और प्रस्तावित चुनावों ने क्षेत्र की संवेदनशीलता, पर्यावरण और वहाँ के लोगों की संवैधानिक आकांक्षाओं के बीच के संघर्ष को उजागर किया है। चर्चा कीजिए कि छठी अनुसूची और पूर्ण राज्य के दर्जे की मांगें लद्दाख के विकास और स्थानीय स्वायत्तता के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं? **(15 अंक, 250 शब्द)**

महत्वपूर्ण तथ्य

Deepavali pollution and how it affects lung function and respiratory health

Athira Elsa Johnson

A toxic smog descended over the country following the Deepavali weekend. Days later, many cities are yet to fully recover from the effects caused by the air pollution. What happens to your respiratory system when it is exposed to hours of pollutants?

Even a few hours of exposure to firecracker smoke can be enough to trigger coughing, wheezing or breathlessness, particularly in people living with asthma or other respiratory conditions. And the effects are not limited to those with an existing diagnosis: high concentrations of particulate matter and gases can irritate the airways in anyone, say doctors.

What the smoke contains

Firecrackers release a mixture of pollutants, including sulphur dioxide, nitrogen oxides, carbon monoxide and particulate matter. The size of the particles determines how deeply they travel into the respiratory system.

"Coarse particles such as PM10 are largely trapped in the nose, throat and larger airways, while fine particles such as PM2.5 can travel deep into the lungs," says Vallabhaneni Viswambhar, senior consultant interventional pulmonologist, Apollo Speciality Hospitals, OMR, Chennai.

R. Sridhar, senior consultant, interventional pulmonology, MGM Healthcare, Chennai, explains that the lungs' natural clearance mechanisms remove some larger particles, but PM2.5 can reach the alveoli, the tiny air sacs where oxygen exchange takes place. Ultrafine particles may also enter the bloodstream.

Even brief exposure to concentrated firecracker smoke can irritate the respiratory tract, particularly in people with sensitive airways, says Dr. Viswambhar. "In people living with asthma or chronic obstructive pulmonary disease (COPD), this may trigger an acute exacerbation or an asthma attack."



Toxic air: Firecrackers release a mixture of pollutants, including sulphur dioxide, nitrogen oxides, carbon monoxide and particulate matter. K.V.S. Giri

Once inhaled, pollutants irritate the airway lining and trigger inflammation. This can increase mucus production, narrow the airways and make them more sensitive.

Mild irritation after short-term exposure is usually reversible once exposure stops. However, recovery may take longer if the airways have become inflamed or if the person has an underlying respiratory condition.

Low wind speeds and temperature inversion can trap pollutants close to the ground, allowing elevated pollution levels to persist for several days after firecracker use, says Sekar Natrajan, senior consultant, interventional pulmonology, SRM Prime Hospital, Ramapuram.

Long-term exposure to fine particulate matter and gases such as nitrogen dioxide has been associated with declining lung function and a higher incidence of chronic respiratory diseases, including COPD. Persistent inflammation can also lead to structural changes in the airways. Experts add that prolonged exposure may contribute to emphysema and pulmonary fibrosis, and increase the risk of lung cancer.

Who is vulnerable?

Children, older adults and people living with heart or lung conditions are particularly susceptible to pollution spikes. Children's lungs are still developing, while lung function and respiratory defence mechanisms can decline with age.

Pregnant women are another vulnerable group. Prolonged exposure to air pollution during pregnancy has been associated with adverse birth outcomes, including low birth weight and premature birth. Experts also point to possible effects on maternal and foetal health.

Minimising exposure is the first step. Experts advise avoiding areas where firecrackers are being burst and reducing outdoor activities when pollution levels are high. If going outdoors is unavoidable, a properly fitted N95 mask can help filter fine particles.

Keeping windows closed during severe pollution episodes and using an air purifier with a HEPA filter, if available, can also reduce indoor exposure.

Experts also recommend avoiding indoor sources of pollution such as smoking, incense and mosquito coils.

While the lungs can recover from mild, short term irritation after exposure stops, repeated or prolonged exposure can accelerate the decline in lung function and contribute to chronic respiratory disease. Improving outdoor air quality and reducing exposure are therefore important even after the immediate Deepavali pollution spike has passed.

(athira.elsa@thehindu.co.in)

PM2.5
PM10

महत्वपूर्ण तथ्य

दीपावली का प्रदूषण और यह फेफड़ों की कार्यप्रणाली तथा श्वसन स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है

- **मुख्य खबर:** दीपावली के बाद देश भर में जहरीला स्मॉग छा गया था, और इसके कई दिनों बाद भी कई शहर वायु प्रदूषण के प्रभावों से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं। जब आपका श्वसन तंत्र प्रदूषकों के संपर्क में आता है, तो क्या होता है?
- **धुएं में क्या होता है:** पटाखों से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर (कणों) सहित कई प्रदूषकों का मिश्रण निकलता है। कणों का आकार यह तय करता है कि वे श्वसन तंत्र में कितनी गहराई तक जाते हैं।
- **फेफड़ों पर असर:** अपोलो स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के डॉ. वल्लभानेनी विश्वंभर बताते हैं कि PM10 जैसे मोटे कण मुख्य रूप से नाक, गले और बड़े वायुमार्ग में फंस जाते हैं, जबकि PM2.5 जैसे बारीक कण फेफड़ों में बहुत गहराई तक जा सकते हैं। एमजीएम हेल्थकेयर के डॉ. आर. श्रीधर बताते हैं कि फेफड़ों की प्राकृतिक सफाई प्रणाली कुछ बड़े कणों को बाहर निकाल देती है, लेकिन PM2.5 एल्वियोली (वायु की छोटी थैलियों जहाँ ऑक्सीजन का आदान-प्रदान होता है) तक पहुँच सकता है। यहाँ तक कि अति-सूक्ष्म कण रक्तप्रवाह में भी प्रवेश कर सकते हैं।
- **लक्षण और जोखिम:** पटाखे के धुएं के संपर्क में कुछ ही घंटे आना खांसी, घरघराहट या सांस की तकलीफ पैदा करने के लिए काफी हो सकता है, खासकर अस्थमा या अन्य सांस की बीमारियों से पीड़ित लोगों में। अस्थमा या क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) से पीड़ित लोगों में यह गंभीर दौरा या अस्थमा अटैक का कारण बन सकता है।
- **दीर्घकालिक प्रभाव:** नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे पार्टिकुलेट मैटर और गैसों के संपर्क में रहने से फेफड़ों की कार्यप्रणाली में गिरावट आती है और COPD सहित पुरानी श्वसन संबंधी बीमारियां बढ़ सकती हैं। लंबे समय तक संपर्क में रहने से एमफिसीमा (emphysema), पल्मोनरी फाइब्रोसिस और फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है।
- **कौन अधिक संवेदनशील हैं?** बच्चे, बुजुर्ग और हृदय या फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित लोग प्रदूषण के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। गर्भवती महिलाओं में लंबे समय तक वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने से समय से पहले जन्म और कम जन्म वजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

बचाव के उपाय:

- पटाखों वाले क्षेत्रों से बचें और जब प्रदूषण का स्तर अधिक हो तो बाहर की गतिविधियां कम करें।
- यदि बाहर जाना जरूरी हो, तो ठीक से फिट होने वाला N55/N95 मास्क बारीक कणों को छानने में मदद कर सकता है।
- गंभीर प्रदूषण के दौरान खिड़कियां बंद रखें और यदि संभव हो तो HEPA फिल्टर वाले एयर प्यूरीफायर का उपयोग करें।
- घर के अंदर धूम्रपान, अगरबत्ती और मच्छर भगाने वाली कॉइल जैसे प्रदूषण के स्रोतों से बचें।

महत्वपूर्ण तथ्य

Retail inflation hits 6.1%, breaches RBI's limit

Almost all categories hit series highs as inflation crosses comfort band for first time in two years

Inflation in food rises to 8.5%; rising fuel takes transport sector to 5.8%, highest in the series

Inflation is mostly supply-driven; festive demand may have added to price pressure, say analysts

T.C.A. Sharad Raghavan
NEW DELHI

Retail inflation rose to 6.1% in October, crossing the Reserve Bank of India (RBI)'s upper threshold for the first time in two years.

The continued uptick in inflation, while driven by food and fuel prices, has now spread to nearly all sectors, data released by the government on Thursday showed.

The RBI targets an inflation rate of 4% with a comfort band of 2% higher or lower than figure.

Inflation as measured by the Consumer Price Index (CPI) last crossed this upper threshold of 6% in October 2024, when it came in at 6.2%. Retail inflation in the corresponding month this year was the highest since then.

The new series of the CPI, with a base year of 2024, has sectoral data that goes back to only January 2026, which means a historical analysis is possible only up to that point. Within that, the latest data show inflation across most categories rose to series highs in October.

The data show that inflation in the food and beverages category rose sharply to 8.5% in October, the highest in the series.

Coupled with this, rising fuel prices meant that inflation in the transport category also rose to 5.8%, a series high.

As a result of accelerating food and transport prices, inflation in the restaurant and accommodation services category jumped to 10.1%, the first time it has come in at double-digits in the new series.



Consumer demands

"Although inflation remains predominantly supply-driven, stronger consumer demand pull associated with festive-season purchases may have added to price pressures, reinforcing the RBI's decision to raise the repo rate by 25 basis points to 5.50%," Pranjul Ghate, economist at Brickwork Ratings said, referring to the Monetary Policy Committee's decision in October.

Apart from food and fuel, the data shows that other aspects of day-to-day life have also seen prices rising at a faster pace.

Clothing and footwear, for example, saw inflation coming in at nearly 5% in October 2026 – the highest in this series – from 3.9% in the previous month.

The 'furnishings, household equipment, and routine household maintenance' category saw inflation quicken to 3.9% this October, also a series high.

Inflation in the health category quickened to 2.05% in October 2026, the highest since January, from 1.4% in September.

The 'housing, water, electricity, gas and other fuels' category saw inflation of 2.9% in October, also the highest in the series.

According to Madan Sabnavis, chief economist at the Bank of Baroda, some food prices could rise further in the coming months.

"The ongoing harvest prospects will throw more light on how food prices behave," Mr. Sabnavis said.

"Area under cultivation was lower for rice, maize, oilseeds, cotton and sugarcane. It has also been reported that pulses production, especially tur, could be lower this time, which can lead to a spike in prices."

Other affected services

Education services saw inflation touch the 4% target for the first time in the new series, while inflation in the information and communication category rose to a series-high of 3.2% in October 2026.

Recreation, sports, and culture saw inflation rise to 2.5% in October 2026, also the highest in the series.

The only category that saw some relief in October was the broad 'personal care, social protection and miscellaneous goods & services' category, which saw inflation ease to 10.1%, the lowest it has been in the new series of the CPI.

"The latest reading makes it increasingly difficult for the MPC to justify holding rates unchanged at its next meeting [in December], strengthening the likelihood of another 25-basis-point hike," Mr. Ghate said.

'STRAINED HOUSEHOLDS' ▸ PAGE 5

YouTube Homework

- CPI
- WPI
- PPI
- IIP
- ICI
- ISP

महत्वपूर्ण तथ्य

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के लिए 4% (±2%) का महंगाई लक्ष्य (inflation target) 2016 में रखा गया था। यह लक्ष्य उर्जित पटेल समिति की सिफ़ारिश पर लागू किया गया था।
- अक्टूबर 2026 में खुदरा महंगाई दर (CPI) बढ़कर 6.09% पर पहुँच गई है, जिसने RBI की 6% की ऊपरी सीमा को पार कर लिया है।

1. महंगाई लक्ष्य का इतिहास और समिति

- कब रखा गया: भारत सरकार ने मई 2016 में RBI अधिनियम, 1934 (धारा 45-ZA) में संशोधन करके फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग (FIT) ढांचे को औपचारिक रूप से अपनाया। इसके तहत 2016 से 2021 तक के लिए 4% (±2% यानी 2% से 6% के बीच) का लक्ष्य तय किया गया था। मार्च 2021 और फिर मार्च 2026 में सरकार ने इस लक्ष्य को मार्च 2031 तक के लिए बरकरार रखा है।
- किस समिति की सिफ़ारिश: यह लक्ष्य उर्जित पटेल समिति (मौद्रिक नीति ढांचे की समीक्षा और सुदृढ़ीकरण के लिए विशेषज्ञ समिति) की सिफ़ारिश पर रखा गया था।

2. अक्टूबर 2026 में महंगाई की स्थिति और जारी डेटा

- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने 12 नवंबर 2026 को अक्टूबर 2026 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI - आधार वर्ष 2024=100) के अनंतिम (provisional) आंकड़े जारी किए हैं। पिछले दो सालों में (अक्टूबर 2024 के बाद) पहली बार महंगाई दर RBI की 6% की सहनशीलता सीमा (tolerance limit) से ऊपर गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य

मुख्य आंकड़े (अक्टूबर 2026 बनाम सितंबर 2026)

श्रेणी	सितंबर 2026 (अंतिम)	अक्टूबर 2026 (अनंतिम)
संयुक्त खुदरा महंगाई (Combined CPI)	5.54%	6.09%
ग्रामीण महंगाई (Rural CPI)	6.08%	6.63%
शहरी महंगाई (Urban CPI)	4.88%	5.41%
संयुक्त खाद्य महंगाई (Combined CFPI)	7.74%	8.94%
ग्रामीण खाद्य महंगाई	8.06%	9.09%
शहरी खाद्य महंगाई	7.18%	8.68%

सेक्टर और वस्तुओं के आंकड़े

- सबसे ज़्यादा महंगी हुई चीज़ें: अक्टूबर 2026 में प्याज़ की महंगाई दर सबसे ज़्यादा 116.22% रही। इसके अलावा लहसुन में 60.74%, चांदी के गहनों में 52.39%, अदरक में 48.32% और नींबू में 47.30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
- अन्य सेक्टर: रेस्टोरेंट और आवास (accommodation) सेवाओं में महंगाई 10.06%, परिवहन (transport) में 5.84%, कपड़े और जूते-चप्पल में लगभग 5%, तथा आवास और ईंधन (housing/fuel) में 2.9% रही।

राज्यों की स्थिति

- सबसे ज़्यादा महंगाई वाले राज्य: बड़े राज्यों में आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा 7.25% महंगाई दर्ज की गई। इसके बाद मध्य प्रदेश (7.19%), ओडिशा (7.17%) और कर्नाटक (7.07%) का स्थान रहा।
- सबसे कम महंगाई: दिल्ली में महंगाई दर 3.80%, अंडमान और निकोबार में 3.46% तथा मिज़ोरम में सबसे कम 2.85% रही।

महत्वपूर्ण तथ्य

Union govt. sanctions 26 roads along LAC in Arunachal

Vijaita Singh
NEW DELHI

Amid continuing face-offs with the Chinese Army along the Line of Actual Control (LAC) in Arunachal Pradesh since late July, the Indo-Tibetan Border Police (ITBP) has sanctioned the construction of new border infrastructure in the northeastern State, a senior government official told *The Hindu*.

Earlier, in February, the Cabinet Committee on Security (CCS) had cleared the third phase of the Indo-China Border Roads (ICBR-III) project.

Under the scheme, as many as 26 roads are to be constructed along the LAC in Arunachal Pradesh, another government official said. The Union Government has not yet officially announced the ICBR-III project or publicly disclosed these details.

This is only the second time after the 2020 Galwan clashes in eastern Ladakh that a critical road infrastructure project has been sanctioned along the border with China.

The first phase of the ICBR was initiated in 2005 when it was decided that the Union Home Ministry would construct 27 priority roads with a total length of 608 km along the border with China.

The second phase of the ICBR, comprising 32 roads with a total length of 683 km, was approved on September 21, 2020, just months after 20 Indian soldiers were killed in violent clashes with the Chinese People's Liberation Army in eastern Ladakh.

Infra plans

Since September, the ITBP has authorised the construction of 15 pedestrian suspension bridges and 18 log bridges in Upper Subansiri and Kurung Kumey districts, covering the areas bordering China in Arunachal Pradesh.



Touchy topography: A bridge under construction in Arunachal Pradesh along the border with China. ABHINAY LAKSHMAN

The project clearance came days after India hosted the 18th BRICS Summit from September 11 to 13 in New Delhi, which was attended by Chinese President Xi Jinping.

A government statement after the meeting said that Prime Minister Narendra Modi emphasised that peace and tranquillity in the border areas remain an essential basis for the continued development of bilateral relations. He underlined the need for both sides to observe existing agreements and understandings on border-related issues.

In December 2020, the Union Home Ministry had approved construction of 18 pedestrian tracks, including foot suspension bridges, log bridges, and staging camps, measuring a total length of 598.27 km in the border areas of Arunachal Pradesh.

'Continuing face-offs'

On October 22 this year, former ITBP Director-General Shatrujeet Kapur mentioned that the "face-off" with Chinese troops "continues at several locations in Arunachal Pradesh."

Addressing the Himveer Samman Samaroah at the Central Training College at Alwar in Rajasthan, Mr. Kapur said, "In the past few days, a situation arose where face-offs happened at several locations in Arunachal and it still continues. Our Shaurya commandos played an exemplary role in this."

The one-hour 13-minute long video recording of Mr. Kapur's speech has since been taken down from the ITBP's official YouTube page.

The tension in Arunachal Pradesh has persisted even though India and China have held three high-level border talks since July.

On August 6, the 36th WMCC (Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs) meeting was held. This was followed by the 25th round of talks between the Special Representatives on the boundary question on August 26 in Beijing, where India was represented by National Security Advisor Ajit Doval.

On September 6, the first-ever Corps Commander-level meetings between the two armies were held in the Eastern Sector at the Vacha-Damai border personnel meeting point in Arunachal Pradesh Such meetings have so far largely been held at the Chushul-Moldo border meeting point in eastern Ladakh, particularly after the Galwan Valley clashes of June 2020.

The Army and the ITBP are deployed along the China border and long-range patrols are regularly sent to the forward areas. Due to the weather conditions, such patrols are only sent between June and October in Arunachal Pradesh.

महत्वपूर्ण तथ्य

- एलओसी (नियंत्रण रेखा - Line of Control) भारत और पाकिस्तान के बीच एक सैन्य नियंत्रण रेखा है, जबकि एलएसी (वास्तविक नियंत्रण रेखा - Line of Actual Control) भारत और चीन के बीच की वास्तविक नियंत्रण रेखा है। इसके अलावा, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (Cabinet Committee on Security - CCS) देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े बड़े फैसले लेने वाली सर्वोच्च सरकारी समिति है, जिसने हाल ही में भारत-चीन सीमा सड़क परियोजना (ICBR) के तीसरे चरण (Phase-III) के तहत अरुणाचल प्रदेश में 26 नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है।

1. एलओसी (LOC) और एलएसी (LAC) में मुख्य अंतर

- दोनों सीमा रेखाएं युद्धविराम के बाद अस्तित्व में आई थीं, लेकिन इनकी भौगोलिक स्थिति और सीमांकन में बड़ा फर्क है:

तुलना का आधार	एलओसी (नियंत्रण रेखा)	एलएसी (वास्तविक नियंत्रण रेखा)
किन देशों के बीच	भारत और पाकिस्तान	भारत और चीन
ऐतिहासिक आधार	1947 के युद्ध के बाद बनी युद्धविराम रेखा (सीजफायर लाइन), जिसे 1972 के शिमला समझौते में एलओसी नाम दिया गया।	1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद दोनों सेनाओं की मौजूदगी के आधार पर बनी रेखा।
सीमांकन	नक्शे पर स्पष्ट रूप से अंकित और दोनों देशों की सेनाओं द्वारा सहमत।	नक्शे पर स्पष्ट रूप से तय नहीं, कई हिस्सों में दोनों देशों के अपने-अपने दावे हैं।
लंबाई और क्षेत्र	लगभग 740 से 776 किलोमीटर लंबी, मुख्य रूप से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में।	भारत के अनुसार 3,488 किलोमीटर लंबी (चीन इसे कम मानता है)। यह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है।

महत्वपूर्ण तथ्य

2. सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (Cabinet Committee on Security) क्या है?

- सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS) भारत सरकार की सबसे शक्तिशाली और सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, जो देश की रक्षा और सुरक्षा से जुड़े मामलों को देखती है।
- सदस्य संरचना: इस समिति की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। इसके अन्य स्थायी सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होते हैं।
- मुख्य कार्य: यह समिति राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े नीतिगत फैसले लेती है। सीमा पर बुनियादी ढांचे के निर्माण, बड़े रक्षा सौदों (हथियारों की खरीद) को मंजूरी देने और आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा करने की जिम्मेदारी इसी के पास होती है।
- महत्व: किसी भी संवेदनशील और बड़े रणनीतिक प्रोजेक्ट (जैसे सीमावर्ती सड़कों के निर्माण) के लिए बजट और अंतिम मंजूरी इसी समिति से मिलती है।

3. भारत-चीन सीमा सड़क परियोजना (ICBR Phase-III) और 26 नई सड़कें

- चीन सीमा पर अपनी सैन्य तैयारियों और संपर्क व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत भारत-चीन सीमा सड़क परियोजना (ICBR) चला रहा है।
- ताजा मंजूरी: द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तीसरे चरण (Phase-III) के तहत अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के साथ 26 नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है।
- रणनीतिक महत्व: अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना (PLA) के साथ बढ़ते तनाव और गतिरोध को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। वर्ष 2020 के गलवान संघर्ष के बाद चीन सीमा पर यह दूसरा सबसे बड़ा सड़क बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट है।
- अतिरिक्त निर्माण (पुल): इन 26 सड़कों के अलावा, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी और कुरुंग कुमेय जिलों में 15 पैदल झूलते पुल (सस्पेंशन ब्रिज) और 18 लकड़ी के पुल (लॉग ब्रिज) बनाने की भी मंजूरी दी है।
- प्रोजेक्ट का उद्देश्य: इन सड़कों और पुलों के बनने से भारतीय सैनिकों, भारी हथियारों और रसद को दुर्गम सीमावर्ती इलाकों तक हर मौसम में तेजी से पहुंचाना आसान हो जाएगा।

महत्वपूर्ण तथ्य

PMO sanctions prosecution of two IAS officers in ₹98-crore T.N. tender irregularities case

Mohamed Imranullah S.
CHENNAI

The Prime Minister's Office (PMO) has accorded sanction to prosecute two IAS officers – K.S. Kandasamy and K. Vijaya Karthikeyan – under the Prevention of Corruption Act, 1988, in connection with the ₹98.25-crore Corporation tender irregularities case in Tamil Nadu, registered primarily against former AIADMK Minister S.P. Velumani, the Madras High Court was informed on Thursday.

Justice N. Anand Venkatesh recorded the submission made by Additional Solicitor General (ASG) A.R.L. Sundaresan, assisted by Central government senior panel counsel V. Chandrasekar, and directed the Directorate of Vigilance and Anti-Corruption (DVAC) to proceed with the process of filing the charge sheet against all the accused in the long-pending corruption case.



The Madras HC proceedings pertain to the case registered primarily against ex-Minister S.P. Velumani. FILE PHOTO

Long-drawn process

Referring to the long-drawn process of obtaining sanction to prosecute the two IAS officers, since the complainant, Jayaram Venkatesan of Arappor Iyakkam, filed a contempt of court petition against the DVAC officials in 2025, the judge said: "It is a classic case of how much of effort had to be put in to obtain sanction to prosecute IAS officers in criminal cases."

"The wheels (of law enforcement) move faster against poor people but for influential people, the wheels hardly move," he said. Last year, the judge issued a series of directions to the State government to send the files to the Centre, and then *suo motu* impleaded the Department of Personnel and Training (DoPT) in New Delhi to make it expedite the process of obtaining sanction.

After the ASG submitted a copy of the sanction order before the court, the judge ordered the deletion of the DoPT from the array of respondents, since it was not a necessary party in the contempt proceedings anymore.

I.A.S.
TN
Tender-
98 Crore
100 Crore
2011-14
308 - 314
(791)
315
323
3141

YouTube Homework

- PMO

महत्वपूर्ण तथ्य

- एक आईएएस (IAS) अधिकारी के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के मामले में जांच शुरू करने से लेकर सज़ा मिलने तक की पूरी प्रक्रिया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act) और अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के तहत चलती है।
- चूंकि आईएएस एक अखिल भारतीय सेवा है, इसलिए इसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की भूमिका होती है। यह पूरी प्रक्रिया 7 मुख्य चरणों में पूरी होती है:

1. शिकायत दर्ज करना (Complaint Filing)

- जांच की शुरुआत किसी नागरिक की शिकायत, किसी सरकारी विभाग की रिपोर्ट, या जांच एजेंसी की गुप्त सूचना से होती है। शिकायत नीचे दी गई संस्थाओं में की जा सकती है:
- राज्य स्तर पर: राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB), स्टेट विजिलेंस विभाग, या लोकायुक्त के पास।
- केंद्र स्तर पर: केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC), सीबीआई (CBI), या लोकपाल के पास (यदि अधिकारी केंद्र में तैनात हो या मामला केंद्र सरकार से जुड़ा हो)।

2. प्रारंभिक सत्यापन (Preliminary Verification)

- शिकायत मिलने के बाद जांच एजेंसी (जैसे सीबीआई या एसीबी) सबसे पहले यह देखती है कि आरोपों में कोई ठोस सच्चाई है या नहीं।
- रिश्वत का मामला (Trap Case): यदि अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ने की बात है, तो एजेंसी बिना किसी पूर्व अनुमति के तुरंत जाल बिछाकर (Trap) कार्रवाई कर सकती है।
- सरकारी फैसलों में भ्रष्टाचार: यदि आरोप किसी टेंडर, ठेके या सरकारी फैसले में गड़बड़ी का है, तो एजेंसी सीधे एफआईआर (FIR) दर्ज नहीं कर सकती।

3. जांच के लिए पूर्व अनुमति (Prior Approval - धारा 17A)

- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत, अधिकारी के सरकारी कामकाज से जुड़े किसी फैसले की जांच शुरू करने से पहले सरकार की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है।
- कौन देता है अनुमति: यदि अधिकारी राज्य में तैनात है, तो राज्य सरकार (मुख्यमंत्री) और यदि केंद्र में तैनात है, तो केंद्र सरकार (DoPT) अनुमति देती है।
- समय सीमा: सरकार को अनुमति देने या मना करने का फैसला 3 महीने (विशेष परिस्थिति में 1 महीना अतिरिक्त, कुल 4 महीने) के भीतर लेना होता है।
- (नोट: यदि शिकायत लोकपाल या लोकायुक्त में की गई है, तो वे बिना सरकार की अनुमति के भी प्रारंभिक जांच के आदेश दे सकते हैं।)

महत्वपूर्ण तथ्य

4. औपचारिक जांच और सबूत इकट्ठा करना (Formal Investigation)

- सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद जांच एजेंसी एफआईआर (FIR) दर्ज करती है और सबूत जुटाती है:
- इस चरण में अधिकारी के घर और दफ़्तर पर छापेमारी (Raid) हो सकती है।
- उनके बैंक खातों, संपत्ति (आय से अधिक संपत्ति), और सरकारी फाइलों की जांच की जाती है।
- गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और अधिकारी से पूछताछ होती है।

5. निलंबन और विभागीय जांच (Suspension and Departmental Inquiry)

- आपराधिक जांच के साथ-साथ सरकार अधिकारी के ख़िलाफ़ विभागीय कार्रवाई भी शुरू करती है:
- निलंबन (Suspension): यदि अधिकारी 48 घंटे से ज़्यादा पुलिस या न्यायिक हिरासत में रहता है, या आरोप बहुत गंभीर हैं, तो राज्य या केंद्र सरकार उन्हें तुरंत पद से निलंबित कर देती है।
- विभागीय जांच: अधिकारी को आरोप पत्र (Charge Memo) दिया जाता है और एक जांच अधिकारी नियुक्त होता है जो सेवा नियमों के उल्लंघन की जांच करता है।

6. मुकदमा चलाने की मंज़ूरी (Sanction for Prosecution - धारा 19)

- जांच पूरी होने के बाद जब एजेंसी के पास पर्याप्त सबूत इकट्ठा हो जाते हैं, तो अदालत में चार्जशीट (Chargesheet) दाखिल करने से पहले एक बार फिर सरकार की मंज़ूरी लेनी पड़ती है।
- केंद्र सरकार का अधिकार: चूंकि आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसलिए उन पर अदालत में मुकदमा चलाने की अंतिम मंज़ूरी केवल केंद्र सरकार (DoPT और प्रधानमंत्री कार्यालय) ही दे सकती है, चाहे अधिकारी किसी भी राज्य में तैनात हो।
- इस मंज़ूरी से पहले केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की सलाह भी ली जाती है।

7. कोर्ट ट्रायल और सज़ा (Court Trial and Punishment)

- केंद्र सरकार से मंज़ूरी मिलने के बाद विशेष सीबीआई या विजिलेंस कोर्ट में मुकदमा चलता है। दोनों पक्षों की दलीलें और सबूत देखने के बाद यदि अपराध साबित हो जाता है, तो दो तरह की सज़ा मिल सकती है:
- अदालत द्वारा सज़ा (Criminal Punishment): भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोष साबित होने पर 3 साल से लेकर 7 साल (और गंभीर मामलों में 10 साल) तक की जेल और भारी जुर्माने की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा भ्रष्टाचार से कमाई गई संपत्ति भी जब्त कर ली जाती है।
- सरकार द्वारा सज़ा (Service Punishment): अदालत से सज़ा होने या विभागीय जांच में दोषी पाए जाने पर राष्ट्रपति के आदेश से अधिकारी को नौकरी से बर्खास्त (Dismissal from Service) कर दिया जाता है, जिससे उनकी पेंशन और अन्य सभी सरकारी सुविधाएं हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

India sees 38% drop in TB mortality since 2015: WHO report

Bindu Shajan Perappadan
NEW DELHI

India has seen a 38% reduction in tuberculosis (TB) mortality since 2015, compared to a global average of 35%, and a 94% treatment success rate among patients with drug-susceptible TB, according to the World Health Organization (WHO)'s Global Tuberculosis Report 2026.

Last year, the South-East Asia Region recorded the largest number of new TB cases (35%), followed by the Western Pacific Region (27%) and the African Region (25%).

Around 88% of new TB cases occurred in 30 countries. India (about a quarter), Indonesia (10%), the Philippines (6.8%), China (6.5%), Pakistan (6.4%), Nigeria (4.9%), the Democratic Republic of the Congo (3.9%) and Bangladesh (3.7%).

Globally, about 50% of people treated for TB and their households face total costs (direct medical expenditures, non-medical expenditures, and indirect costs such as income losses) that are catastrophic (greater than 20% of total household income).

People with compromised immune systems, such as those living with HIV, undernutrition or diabetes, or people who use tobacco have a higher risk of falling ill.

High toll

The report showed a total of 1.13 million people died from TB in 2025. Multi-drug-resistant TB remains a public health crisis and a health security threat.

Between December 7, 2024 and November 8, 2026, the TB Mukt Bharat Abhiyaan achieved significant progress, identifying and bringing over 25 crore individuals within the scope of screening.

WHO
↳ Global Tuberculosis Report 2026

TB

2015 — 2026
↳ 11
38%

YouTube Homework

↳ TB
Tuberculosis

महत्वपूर्ण तथ्य

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने 12 नवंबर 2026 को ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2026 जारी की है, जो दुनिया भर के 187 देशों से प्राप्त वर्ष 2025 के आंकड़ों पर आधारित है। यह रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक स्तर पर टीबी के मामलों और मौतों में कमी आ रही है, लेकिन 2030 तक टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को पाने के लिए गति अभी भी धीमी है।

वैश्विक स्तर पर मुख्य आंकड़े (Global Data)

- कुल नए मामले. वर्ष 2025 में दुनिया भर में अनुमानित 1.06 करोड़ (10.6 मिलियन) लोग टीबी से बीमार हुए। यह 2024 की तुलना में लगभग 75,000 कम है।
- संक्रमण की दर. वैश्विक टीबी संक्रमण दर (इंसिडेंस रेट) प्रति एक लाख आबादी पर 129 नए मामले रही। 2015 से 2025 के बीच इसमें कुल 14 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।
- टीबी से होने वाली मौतें. वर्ष 2025 में टीबी के कारण अनुमानित 11.3 लाख (1.13 मिलियन) लोगों की मृत्यु हुई। यह संक्रामक रोगों से होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है।
- मृत्यु दर में गिरावट. 2015 की तुलना में वैश्विक टीबी मृत्यु दर में 35 प्रतिशत की कमी आई है।
- प्रभावित वर्ग. कुल मामलों में 54 प्रतिशत पुरुष, 35 प्रतिशत महिलाएं और 11 प्रतिशत बच्चे शामिल हैं।
- जांच और छूटे हुए मामले. 1.06 करोड़ बीमार लोगों में से 84 लाख (8.4 मिलियन) लोगों की पहचान कर उनका पंजीकरण किया गया। शेष लगभग 22 लाख मामलों की या तो जांच नहीं हो पाई या वे दर्ज नहीं हो सके।
- दवा-प्रतिरोधी टीबी (DR-TB). वर्ष 2025 में रिफाम्पिसिन-प्रतिरोधी टीबी के अनुमानित 3.70 लाख नए मामले सामने आए। इनमें से केवल 42 प्रतिशत मरीजों को ही उपचार मिल पाया।
- उपचार की सफलता और फंडिंग. सामान्य टीबी के इलाज की वैश्विक सफलता दर लगभग 90 प्रतिशत रही। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में टीबी की रोकथाम और इलाज के लिए कुल 6.6 अरब डॉलर का वित्तपोषण हुआ, जिसमें घरेलू बजट में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई।

महत्वपूर्ण तथ्य

भारत के संदर्भ में मुख्य आंकड़े (India Context)

- वैश्विक हिस्सेदारी. दुनिया भर में टीबी के कुल मामलों में अकेले भारत की हिस्सेदारी लगभग 25 प्रतिशत (एक चौथाई) है, जो किसी भी देश में सर्वाधिक है।
- मृत्यु दर में बड़ी गिरावट. वर्ष 2015 से 2025 के बीच भारत में टीबी से होने वाली मौतों में 38 प्रतिशत की रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। यह 35 प्रतिशत के वैश्विक औसत से बेहतर प्रदर्शन है।
- मामलों और मौतों की संख्या. राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत वर्ष 2025 में भारत में 25.3 लाख टीबी मरीजों की पहचान की गई और इस संक्रमण से 2.63 लाख मौतें दर्ज की गईं। वर्ष 2024 में 26.18 लाख मामले और 3 लाख से अधिक मौतें दर्ज हुई थीं।
- उच्च उपचार सफलता दर. भारत में दवा-संवेदनशील टीबी मरीजों के बीच उपचार की सफलता दर 94 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो वैश्विक औसत से काफी अधिक है।
- टीबी मुक्त भारत अभियान. इस अभियान के तहत 25 करोड़ से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। इसके लिए 11 करोड़ से ज्यादा छाती के एक्स-रे और 3 करोड़ मॉलिक्यूलर टेस्ट किए गए, जिससे 48.64 लाख मामलों (जिनमें 14.97 लाख बिना लक्षण वाले मरीज थे) का पता लगाने में मदद मिली।
- घरेलू निवेश और तकनीक. भारत अपने टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की 96 प्रतिशत वित्तीय आवश्यकताओं को घरेलू संसाधनों से पूरा कर रहा है। सरकार ने मरीजों की पहचान और देखभाल के लिए एआई (AI) आधारित एक्स-रे, निक्षय पोषण योजना और निक्षय मित्र जैसी पहलों को बड़े पैमाने पर लागू किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

Swabbing public transport to identify urban microbiomes

A recent study in the Chennai Metro Rail showed a wide range of microbes found on high-touch surfaces, though researchers said there was no cause for fear and no immediate reason to act. It showed that the city had a distinctive 'transit biome' — influenced by its coastal climate, humidity, urban density and nearby agricultural activity

Ramya Kannan

From waste-water surveillance to public transport surfaces, mankind is constantly on the lookout for diverse microbial sources to use, to understand and microbial resistance patterns in a particular society. The latest in the urban transport systems sweep, performed at Chennai Metro Rail stations, showed that Chennai had a distinctive 'transit biome' — influenced by the city's coastal climate, humidity, urban density and relatively nearby agricultural activity.

A team of researchers from IIT Madras swabbed 90 samples from 12 stations and trains on Chennai Metro's Blue and Green Lines in December 2021 and January 2022, targeting four high-touch surfaces: metro handrails (handrails), ticket-vending kiosks, train handrails (grabs), and ticket counters. The team swabbed 90 samples from 12 stations and trains and after quality control, 47 samples were sequenced using whole-genome metagenomic sequencing. Metagenomics is defined as the direct genetic analysis of genomes contained within an environmental sample.



Understanding patterns Train waste-water surveillance in public transport surfaces, mankind is constantly on the lookout for diverse microbial sources to use, to understand and microbial resistance patterns in a particular society. K. MURALI KUMAR

City's signature

The researchers, in a paper published in the peer-reviewed journal *Msphere*, said they found a distinct Chennai-specific microbial community, with strains being the most microbially diverse surface, and detected generally low but widespread antimicrobial resistance (AMR) genes — especially for sulfonamide and rifamycin resistance. "Understanding these environments is crucial for public health, especially in light of the COVID-19 pandemic and growing concerns about antimicrobial resistance (AMR). This study is the first of its kind to investigate the microbial communities and the presence of AMR genes in the Chennai Metro system," the authors said.

Talking about the research, Karthik Raman, of the Department of Biotechnology, Bhupat and Jyoti Mehta School of Biosciences, and Centre for Integrative Biology and Systems Medicine, Wadhwani School of Data Science and Artificial Intelligence, IIT Madras, Chennai, said, the key aspect of the study was the discovery of the microbial signature for Chennai.

"It has been done in many metro systems across the world. Every city has a different signature, influenced by the city itself. As far as CMRL goes, there is no immediate worry for the people at this point. The metro train is routinely sanitised. Also our sampling work was done during the COVID-19 pandemic, so there was regular sanitisation in the stations." In fact, he adds, the sanitisation was so thorough that many samples actually failed the quality control process.

Researchers found that nine 'unique core' species were common in Chennai that were not core or sub-core in other global cities. These included salt-tolerant, tropicalised, soil/water, poultry-associated, and human-skin-associated bacteria, suggesting influences from Chennai's coastal climate, humidity, urban density, and nearby agricultural activity. "We also found, surprisingly that the tracks, and not the train bays or poles were the most diverse surfaces."

The study uncovered 356 AMR gene families across 26 drug classes, and strong biotic sulfonamide- and rifamycin-resistance genes had a comparatively higher abundance. Dr. Raman explains: "We have a sort of a baseline data, on microbes in key public transport in Chennai. We also have a pathogen support toolkit — all lists microbes get support from microbes nearby. We have quantified the metabolic support that microbial communities share, CMRL stations, and routes provide to persistent or keystone pathogens. We have looked at the dynamic interactions between these microorganisms."

The researchers said: "Despite their relatively low abundance, several AMR families were widely distributed across the data set, with over 85% of samples containing at least one gene associated with AMR, including families linked to efflux pumps, multidrug resistance, and sulfonamides."

This make a case for routine microbial and AMR surveillance in Indian transit systems. This study lays a foundation for understanding the urban microbiome in India, emphasising distinct regional characteristics and underscoring the need for sustained monitoring to mitigate disease transmission risks in high-density transit settings.

A global recode

Chennai has only followed the experience of transport and transit point surveillance for AMR across the world. In 2015, a project called PathSTrip was launched in the United States. The primary goal was to study the microbiome of an urban, metropolitan environment — New York City. In the summer of 2015, 466 NYC subway stations were sampled. Interestingly, nearly half (48%) the DNA matched no known organisms, it was reported.

The success of the project led to the creation of the Metagenomics and Metadesign of Subways and Urban Biomes (MetaSUB) International Consortium in 2016, initiated by Christopher Mason, an associate professor at Weill Cornell Medicine and Evan Afshin, a medical student at New York Medical College. The consortium officially launched with Global City Sampling Day on June 21, 2016.

2016 marked the first annual event of simultaneous sampling around the world, spanning six continents, 32 countries and 60 cities, the event collected more than 4,000 samples of DNA, RNA and microbes from surfaces in subways, buses, airports and other well-trafficked public transit systems. Today, the MetaSUB International Consortium aims to create geospatial metagenomic and forensic genetic maps, identify and track antimicrobial resistance markers (AMRs) in the urban built environment and identify novel biosynthetic gene clusters (BCGs) for drug discovery.

David Danko et al, in a 2021 paper in *Cell*, "A global metagenomic map of urban microbiomes and antimicrobial resistance" analysed the data sets from two Global City Sampling days (in 2016 and 2018) and a pilot study. They yielded a global atlas of 4,728 metagenomic samples from mass transit systems in 60 cities over three years, representing the first systematic, worldwide catalogue of the urban microbial ecosystem. The researchers wrote: "We identified 4,246 known species of urban microorganisms and a consistent set of 31 species found in 95% of samples that were distinct from human microcosmos. Profiles of AMR genes varied widely in type and density across cities. Cities showed distinct microbial taxonomic signatures that were driven by climate and geographic differences."

Resistant bacteria

A 2020 study reported in the *Journal of Antimicrobial Chemotherapy*, designed to understand the prevalence of antibiotic-resistant bacteria in the Beijing subway environment, for instance, found the potential transmission of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae in a public transportation environment. This is a type of Gram-negative bacterium that has developed resistance to carbapenems, which are a class of powerful 'last-line' antibiotics used to treat severe multi-drug resistant infections. The study on the Hong Kong Mass Transit Railway System proceeded on the fact that the "skin functions as the primary interface between the human body and the external environment." "To understand how the microbiome varies within urban mass transit and influences the skin microbiota, we profiled the human palm microbiome after contact with handrails," the researchers wrote.

The study provided an important reference for future public health strategies to mitigate antibiotic and cross-border pathogen and Antibiotics Resistance Genes transmission.

Swabbing public transit networks in Belgrade, the London Underground, and networks in East Africa and South Asia has also helped identify the baseline microbiome associated in these nations.

THE GIST

- A team of researchers from IIT Madras swabbed 90 samples from 12 stations and trains on Chennai Metro's Blue and Green Lines in December 2021 and January 2022, targeting four high-touch surfaces: station handrails, train handrails (grabs), ticket-vending kiosks, train handrails (rails), and ticket counters
- The researchers, in a paper published in the peer-reviewed journal *Msphere*, said they found a distinct Chennai-specific microbial community, with strains being the most microbially diverse surface, and detected generally low but widespread antimicrobial resistance (AMR) genes
- Swabbing public transit networks in Belgrade, the London Underground, and networks in East Africa and South Asia has also helped identify the baseline microbiome associated in these nations

ramya.kannan@thehindu.co.in

YouTube Homework

- **AMR (Anti Microbial Resistance)**

महत्वपूर्ण तथ्य

शहरी सूक्ष्मजीवों (Urban Microbiomes) की पहचान के लिए सार्वजनिक परिवहन की स्वैबिंग (नमूने लेना)

- **मुख्य खबर:** चेन्नई मेट्रो रेल में किए गए एक हालिया अध्ययन में अधिक स्पर्श की जाने वाली सतहों (high-touch surfaces) पर विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीव (microbes) पाए गए हैं। हालांकि, शोधकर्ताओं का कहना है कि इससे डरने या तुरंत कोई कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह अध्ययन दर्शाता है कि शहर का अपना एक विशिष्ट 'ट्रांजिट बायोम' (transit biome) है, जो तटीय जलवायु, आर्द्रता, शहरी घनत्व और आस-पास की कृषि गतिविधियों से प्रभावित है।
- **अध्ययन का विवरण:** आईआईटी मद्रास (IIT Madras) के शोधकर्ताओं की एक टीम ने दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में चेन्नई मेट्रो की ब्लू और ग्रीन लाइनों के 12 स्टेशनों और ट्रेनों से 96 नमूने लिए। इसके लिए चार प्रमुख सतहों—स्टेशन की रेलिंग, टिकट वेंडिंग कियोस्क, ट्रेन के हैंडरेल (रॉड) और टिकट काउंटरों को लक्षित किया गया। गुणवत्ता नियंत्रण के बाद, 'होल-जीनोम मेटाजीनोमिक सीक्वेंसिंग' (whole-genome metagenomic sequencing) का उपयोग करके 47 नमूनों का विश्लेषण किया गया।
- **शहर की विशिष्ट पहचान (City's signature):** *mSphere* जर्नल में प्रकाशित इस शोध पत्र के अनुसार, चेन्नई में एक विशिष्ट सूक्ष्मजीव समुदाय पाया गया है, जिसमें टिकट वेंडिंग कियोस्क की सतह पर सबसे अधिक विविधता वाले सूक्ष्मजीव मिले (ट्रेन की छड़ों या खंभों की तुलना में भी अधिक)। अध्ययन में पाया गया कि चेन्नई में 9 'अद्वितीय-प्रमुख' (unique-core) प्रजातियां आम थीं जो अन्य वैश्विक शहरों में नहीं देखी गई।
- **एंटी-माइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR):** शोधकर्ताओं ने 25 दवा वर्गों में 206 एंटी-माइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR - दवा प्रतिरोधी) जीन परिवारों की पहचान की। विशेष रूप से सल्फोनामाइड (sulfonamide) और रिफैम्पिसिन (rifampicin) प्रतिरोधी जीन की प्रचुरता अपेक्षाकृत अधिक पाई गई। 80% से अधिक नमूनों में AMR से जुड़ा कम से कम एक जीन मौजूद था।
- **वैश्विक संदर्भ (Global Swab):** इससे पहले 2013 में न्यूयॉर्क शहर में 'PathoMap' नामक परियोजना शुरू की गई थी, जिसके बाद 2015 में 'MetaSUB' इंटरनेशनल कंसोर्टियम बना। इसका उद्देश्य दुनिया भर के 60 से अधिक शहरों के सबवे, बसों और हवाई अड्डों से सूक्ष्मजीवों के नमूने लेकर वैश्विक मानचित्र तैयार करना और एंटी-माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को ट्रैक करना है। बीजिंग, लंदन अंडरग्राउंड, हांगकांग, बेलग्रेड, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण एशिया के परिवहन नेटवर्क में भी इसी तरह के अध्ययन किए गए हैं।
- **निष्कर्ष:** आईआईटी मद्रास के डॉ. कार्तिक रमन के अनुसार, यात्रियों के लिए डरने का कोई कारण नहीं है क्योंकि मेट्रो मार्ग की नियमित रूप से सफाई (sanitisation) की जाती है। यह अध्ययन भविष्य में जनस्वास्थ्य की निगरानी और घनी आबादी वाले पारगमन स्थलों पर रोग संचरण के जोखिमों को कम करने के लिए एक आधारभूत डेटा (baseline data) प्रदान करता है।

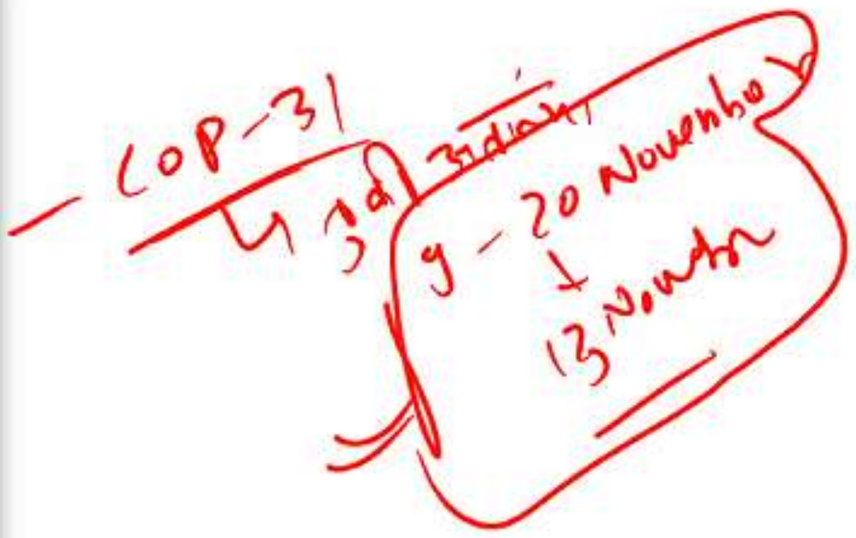
महत्वपूर्ण तथ्य

New deal

Nations must deliver on past promises before committing to lofty climate goals

The 31st Conference of Parties (COP) began this week in Antalya, Türkiye. Hosted by Türkiye and negotiations presided over by Australia, the run up to the gathering saw ministerial delegations visit Fiji and Tuvalu. This was to serve as a stark reminder of the purpose of COPs, namely that it was small island nations that are most vulnerable to warming from rising greenhouse gas emissions. However, the opening days have belied this sense of urgency. Prominent world leaders, even from the European countries who as a group champion the cause most vociferously, have chosen to skip the meet. The agenda and pre-summit expectations suggest that the main concerns this year are likely to be about delivering on existing commitments such as delivering $300 billion a year by 2035, which was decided at COP29 in Baku, as well as the COP30 call to triple the adaptation finance during that interval. However, deciding how these climate funds will practically flow has been deferred to COP32. The second global stocktake, a periodic check on progress under the Paris Agreement, begins at COP31, but the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) has dithered on a timeline for the next reports that will serve as the scientific push to policy makers to accelerate efforts towards keeping a rise in temperatures below 2°C, and more ambitiously 1.5°C.

The previous edition of COP30 concluded without a formal roadmap away from fossil fuels – a step back from the COP28 consensus in Dubai. There is a voluntary roadmap ahead of COP31 but it is out of the formal negotiating text. In the background of the West Asia war, the withdrawal of the United States from the Paris Agreement and financial strain writ large over Europe, funds are a challenge as evidenced in the recent Loss and Damage fund approval to Nepal of $21 million when the ask is in billions. COP31 president, Murat Kurum has laid an electrification target, which is to raise electricity's share from 23% of total energy consumption to 35% by 2035. India has already refused to sign such a pledge and insisted on predictable climate finance, technology transfer, and nationally determined approaches to climate mitigation. These negotiations have a character of their own and deliberating nations must strive to get nations to deliver on past promises rather than commit to new lofty targets.



YouTube Homework

- UNFCCC
- UNEP
- UNDP

महत्वपूर्ण तथ्य

नया सौदा (New Deal) - COP31 जलवायु सम्मेलन

- **मुख्य बैठक:** तुर्की के अंताल्या में 31वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP31) की शुरुआत हुई है, जिसकी मेजबानी तुर्की कर रहा है और वार्ता की अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया कर रहा है।
- **मुख्य मुद्दे और वादे:** इस सम्मेलन का मुख्य ध्यान पुराने वादों को पूरा करने पर है, जैसे कि COP29 में तय किए गए 2035 तक प्रति वर्ष 300 बिलियन डॉलर देना। हालांकि, इन फंडों के वितरण का व्यावहारिक तरीका COP32 तक टाल दिया गया है।
- **चुनौतियाँ:** पश्चिमी एशिया के युद्ध, पेरिस समझौते से अमेरिका के हटने और यूरोप में वित्तीय संकट के कारण फंड जुटाना एक बड़ी चुनौती बन गया है।
- **भारत का रुख:** COP31 के अध्यक्ष मूरत कुरुम ने 2035 तक कुल ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी 23% से बढ़ाकर 35% करने का लक्ष्य रखा है। भारत ने इस तरह के समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है और अनुमानित जलवायु वित्त, तकनीक के हस्तांतरण तथा जलवायु से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित दृष्टिकोण पर जोर दिया है।
- **निष्कर्ष:** बड़े नए लक्ष्य तय करने से पहले देशों को अपने पुराने वादों को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए।

COP 31 (2026)

- **स्थान:** अंताल्या (Antalya), तुर्किए (तुर्की) के एक्सपो सेंटर में
- **तिथि:** 9 से 20 नवंबर 2026
- **अध्यक्षता / मेजबानी:** इसकी मेजबानी **तुर्किए** (तुर्की) द्वारा की जा रही है और वार्ता की अध्यक्षता **ऑस्ट्रेलिया** कर रहा है। तुर्की के पर्यावरण मंत्री **मुराद कुरुम** (Murat Kurum) इसके अध्यक्ष हैं। UN-Habitat +3

COP 32 (2027)

- **स्थान:** अदीस अबाबा (Addis Ababa), इथियोपिया
- **तिथि:** 8 से 19 नवंबर 2027
- **अध्यक्षता / मेजबानी:** यह सम्मेलन अफ्रीकी समूह (African Group) की ओर से **इथियोपिया** में आयोजित होगा। इथियोपिया के विदेश मंत्री डॉ. **गिडियन तिमोथवोस** (Gedion Timothewos) को COP 32 का अध्यक्ष-नामित (President-Designate) नियुक्त किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

India and U.K. are turning climate ambition into action



Ben Mellor

Acting British High Commissioner to India

Next week, Mumbai will become the stage for one of the world's boldest climate ideas. The largest ever Earthshot Prize edition will bring together innovators, investors, businesses, policymakers and young people to turn environmental solutions into impact at scale. Five winners will each receive £1 million to accelerate their work.

It all began with a simple but powerful idea: that human ingenuity, innovation and optimism can help repair our planet. Founded by His Royal Highness The Prince of Wales, The Earthshot Prize seeks solutions capable of delivering transformative environmental impact. Since the Prize was launched in 2020, India has produced more Earthshot finalists and winners than any other country (nine finalists including four winners). This year two of the 15 finalists are based in India. As the Prize arrives in Mumbai, India's growing influence in clean growth and climate innovation will be on full display.

I have seen what this kind of partnership can achieve. I began my career as a diplomat working on the Montreal Protocol, when governments, companies, scientists and NGOs came together to tackle the hole in the ozone layer. It worked. Almost all ozone-depleting substances have been phased out and the ozone layer is on track to recover within decades. However, climate change is a far bigger and more complex challenge.

The need to accelerate climate action

The urgency behind Earthshot's message is stronger than ever. This year, the climate crisis has been exacerbated by El Niño, with conflict-driven energy shocks being felt globally. The surest way to safeguard our energy security and economic growth is to accelerate the transition to clean energy.

The U.K.-India climate partnership shows what delivery can look like in practice. Both our countries recognise that the shift to cleaner growth is not separate from the pursuit of prosperity. That is why climate and clean energy cooperation sit at the heart of the U.K.-India Vision 2035.

The U.K.-India climate partnership shows what delivery can look like in practice. Both our countries recognise that the shift to cleaner growth is not separate from the pursuit of prosperity

India's progress speaks for itself. Non-fossil fuel sources now account for more than half of India's installed power capacity – five years ahead of its 2030 target; it is aiming for 500 GW of non-fossil fuel capacity by 2030. Through the International Solar Alliance and the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, India is shaping global response. Meanwhile, the U.K. has also cut its greenhouse gas emissions by more than half since 1990 while growing our economy.

Earlier this month, the U.K. was proud to be a partner country at the Bharat Renewable Energy Summit and Expo 2026, which showcased the dynamism of India's clean energy sector.

India's Central Electricity Regulatory Commission and Ofgem (the U.K.'s Office of Gas and Electricity Markets) are working together on electricity market reform, and a joint offshore wind taskforce is supporting the development of the sector in India. The U.K. is learning from India's energy stack on data sharing across the energy system.

Financing climate action

Such innovation changes the world only if it is financed at scale. Last year, our governments launched the India-U.K. Climate Finance Initiative to help scale climate investment, unlock green growth and create new financing opportunities in both countries. The U.K. is already mobilising significant capital for India's transition. Our £330 million capital investment portfolio, in partnership with the Government of India, has leveraged more than £3.5 billion for green and inclusive businesses and technology start-ups. British International Investment (BII) has backed more than 600 businesses and committed $1.1 billion to climate-focused investments in India since 2022, making India its largest market. This money is funding initiatives that people in India will be witnessing and using in their day-to-day life such as electric buses, grid-scale batteries and the next generation of clean-tech start-ups.

A global security issue

Climate is also a security issue. At the UN General Assembly in September, U.K. Foreign Secretary Ed Miliband co-convened foreign Ministers to discuss climate and nature crises as national security challenges.

It is an agenda the U.K. and India share, reflected in our co-chairing of the UN Disaster Risk Reduction Senior Officials' Meeting in New Delhi in October. Both India's National Disaster Management Authority and the U.K.'s Centre for Disaster Protection, working together, are strengthening disaster risk financing, including assessing the feasibility of a sovereign disaster risk pool.

Earthshot coincides with COP31 in Antalya, Türkiye, where governments will meet to turn the Paris Agreement into delivery. The U.K. will work with India and other partners to accelerate the electrification of transport and industry, unlock finance, and keep the goal of limiting warming to 1.5 degrees Celsius within reach.

The Montreal Protocol showed that the world can fix a planetary problem when it chooses to. The innovators gathering in Mumbai are showing what is possible today. The task now is for governments, investors and businesses to back them with capital and the policy certainty that lets good ideas grow. From Mumbai to Antalya, the message is clear: climate action cannot wait. The U.K. and India are not just talking about the future we need, we are building it. We invite others to build it with us.



महत्वपूर्ण तथ्य

- अर्थशॉट प्राइज (Earthshot Prize) 2026 एक प्रतिष्ठित वैश्विक पर्यावरण पुरस्कार है, जो पहली बार भारत के मुंबई शहर में आयोजित हो रहा है। यह इस पुरस्कार का छठा (6th) संस्करण है और इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के ऐसे नवीन (innovative) और बड़े स्तर पर लागू होने वाले समाधानों को पहचानना और सहयोग देना है, जो हमारी पृथ्वी को बचाने में मदद कर सकें।

अर्थशॉट प्राइज मुंबई 2026 क्या है?

- 5-दिवसीय कार्यक्रम और तारीखें। द अर्थशॉट प्राइज (The Earthshot Prize) ने मुंबई में अपने अब तक के सबसे बड़े पांच-दिवसीय (five-day) उत्सव का आयोजन किया है। इसमें 15 नवंबर 2026 को भी वैश्विक नेताओं, इनोवेटर्स और युवाओं के लिए विशेष प्री-इवेंट्स और कम्युनिटी प्रोग्राम शामिल हैं।
- मुख्य समिट और अवॉर्ड्स नाइट (16–17 नवंबर)। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, मुख्य अर्थशॉट प्राइज समिट 16 नवंबर को है, जिसमें 'द चिल्ड्रन्स अर्थशॉट' और 'इम्पैक्ट असेंबली' जैसे बड़े सत्र होंगे। इस पूरे कार्यक्रम का समापन 17 नवंबर को मुख्य 'अवॉर्ड्स नाइट' (Awards Night) के साथ होगा, जिसका वैश्विक प्रसारण 30 नवंबर को प्राइम वीडियो (Prime Video) पर किया जाएगा।
- पुरस्कार राशि और श्रेणियां। इसमें 15 फाइनलिस्ट में से 5 विजेताओं को चुना जाएगा और प्रत्येक विजेता को अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए £1 मिलियन (10 लाख पाउंड) की अनुदान राशि (grant) मिलेगी। ये पुरस्कार पांच श्रेणियों में दिए जाते हैं — प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर नेचर (प्रकृति की रक्षा), क्लीन अवर एयर (स्वच्छ हवा), रिवाइव अवर ओशन्स (महासागरों का पुनरुद्धार), बिल्ड अ वेस्ट-फ्री वर्ल्ड (कचरा-मुक्त दुनिया), और फिक्स अवर क्लाइमेट (जलवायु सुधार)।
- वैश्विक और भारतीय भागीदारी। इस समारोह की मेजबानी करण जौहर करेंगे और इसमें सचिन तेंदुलकर, आलिया भट्ट, रामी मालेक और श्रेया घोषाल जैसी हस्तियां शामिल होंगी। भारत की ओर से महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी (Mahindra Last Mile Mobility) और महिला हाउसिंग ट्रस्ट (Mahila Housing Trust) भी इस साल के फाइनलिस्ट में शामिल हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

यूनाइटेड किंगडम (UK) की क्या भूमिका है?

- संस्थापक और नेतृत्व। इस पुरस्कार की स्थापना साल 2020 में यूके के प्रिंस विलियम (प्रिंस ऑफ वेल्स) और उनकी 'रॉयल फाउंडेशन' (Royal Foundation) द्वारा की गई थी। प्रिंस विलियम स्वयं इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए मुंबई आ रहे हैं।
- यूके-भारत जलवायु साझेदारी। यूके और भारत इस मंच के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा (clean energy) और जलवायु नवाचार में अपनी साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। यूके की 'यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर' जैसे संस्थान भी इसके शोध और ज्ञान-साझाकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं।

संयुक्त राष्ट्र (United Nations - UN) की क्या भूमिका है?

- UN SDGs पर आधारित। अर्थशॉट प्राइज के पांचों लक्ष्य या श्रेणियां सीधे तौर पर संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (UN Sustainable Development Goals) से प्रेरित हैं। इसका उद्देश्य 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के जलवायु और पर्यावरण लक्ष्यों को पूरा करने की गति को तेज करना है।
- वैश्विक नीति सहयोग। हालांकि यह संयुक्त राष्ट्र का कोई आधिकारिक पुरस्कार नहीं है, लेकिन इसके कार्यक्रमों में संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। यह मंच संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक जलवायु एजेंडा (जैसे पेरिस समझौता और COP शिखर सम्मेलन) को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए एक सेतु (bridge) का काम करता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

'India will remain a trusted partner for global investors'

Amid global uncertainties, India is doing all it can to ensure safety of the investors' money, even as wars rage in other parts of the world, says Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal

V. Raghavendra
VISAKHAPATNAM

Seeking to assuage fears over the safety of Foreign Direct Investments (FDI) due to the likely impact of global uncertainties, Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal said India had been and would remain a trusted partner and reliable destination for investors even as wars raged in other parts of the world.

The ongoing conflicts cast their shadow on international trade, but India was an exception, with its stable policies and governance that would never let the investors down, he asserted. Participating as the chief guest in the inaugural session of the 31st CII Partnership Summit 2026 here on Thursday, Mr. Goyal said the world was witnessing multiple crises, challenges and intense competition, but India was committed to standing by investors during these tough times.



Commerce Minister Piyush Goyal shares a lighter moment with A.P. CM N. Chandrababu Naidu at the CII Partnership Summit. K.R. DEEPAK

The investor community could be assured of the business environment even during the present times, as the Government of India was doing all it could to ensure the safety of the money they were pumping into various projects, he asserted.

Mr. Goyal said India would fully respect and protect Intellectual Property Rights and extend cooperation to innovators and investors. "India would never steal technology," he stated, promising industries full support in manufacturing high-quality products at competitive costs and at a greater speed.

While foreign investments poured in, India's skilled youth were making a significant contribution to the country's GDP growth by leveraging on their skills and capabilities to a phenomenal effect, the Minister said.

31st CII Partnership Summit

महत्वपूर्ण तथ्य

- 31वाँ CII पार्टनरशिप समिट 2026 आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) में आयोजित हो रहा है। इसमें CII का अर्थ भारतीय उद्योग परिसंघ (Confederation of Indian Industry) है, जो भारत का एक प्रमुख गैर-सरकारी और गैर-लाभकारी व्यापारिक संगठन है।

इस समिट से जुड़ी सभी मुख्य जानकारियाँ नीचे दी गई हैं:

- CII क्या है. भारतीय उद्योग परिसंघ (Confederation of Indian Industry) भारत में उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाने का काम करता है। यह सरकार और व्यापार जगत के बीच एक सेतु (कड़ी) के रूप में नीति निर्माण और वैश्विक आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देता है।
- कब से कब तक होना है. मुख्य शिखर सम्मेलन 12 और 13 नवंबर 2026 को आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा 11 नवंबर 2026 को इसके प्री-इवेंट (Summit Prelude) सत्र रखे गए थे।
- इसे कौन करा रहा है. इसका आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस आयोजन की मेजबानी आंध्र प्रदेश सरकार कर रही है।
- अध्यक्षता कौन करेगा. इस समिट की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू इसके सह-अध्यक्ष (Co-Chair) के रूप में भूमिका निभा रहे हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

Russian oil imports touch record €6.4 bn in Oct.

Press Trust of India
NEW DELHI

India's purchases of Russian fossil fuels surged to a record €6.4 billion in October, driven by a sharp increase in crude oil imports, helping Moscow push its fossil fuel export revenues to their highest monthly level since December 2022 despite Western sanctions.

"India was the second-largest buyer of Russian fossil fuels in October 2026, importing a total of €6.4 billion of Russian hydrocarbons, its highest monthly total in data going back to January 2022. Crude oil constituted 91 % of India's purchases, totalling €5.8 billion. Coal (€333 million) and oil products (€232 million) constituted the remainder of its monthly Russian imports," according to a monthly analysis by the Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).

China remained the largest global buyer of Russian fossil fuels, accounting for 51% (€10.7 billion) of Russia's export revenues from the top five importers.

"India's imports of Russian crude oil rose in October 2026, up 10% month-on-month. Russian crude imports rose at all three of India's largest importing refineries: (Nayara Energy's) Vadinar (up 12 % month-on-month), (Reliance Industries Ltd's) Jamnagar (up 22%), and (Indian Oil Corporation Ltd.'s) Paradip (up 28%)," CREA said. "This increase has once again made the Jamnagar refinery the biggest importer of seaborne Russian crude."



India was the second-largest buyer of Russian fossil fuels in October 2026.

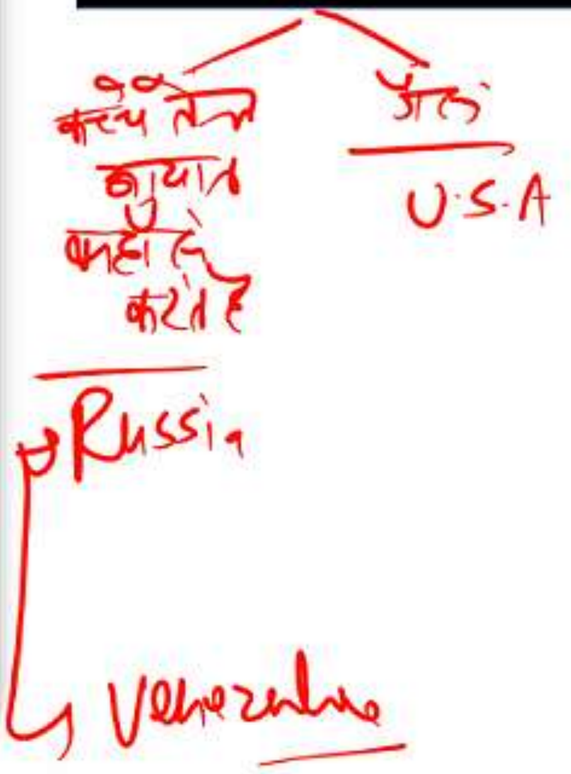
The EU was the third-largest buyer of Russian fossil fuels, accounting for 11 % (€2.2 billion) of Russia's export revenues from the top five importers in October 2026. Refineries in India, Turkiye, and Brunei that use Russian crude exported €1.6 billion of oil products to countries that imposed sanctions on Russia for its February 2022 invasion of Ukraine. "The destinations include the EU (€1.2 billion), Australia (€271 million), the U.S. (€94 million), and New Zealand (€23 million). An estimated €389 million of these products were refined from Russian crude."

According to CREA, Russia's fossil fuel export revenues surged to their highest monthly level in October since December 2022, rising 14% from the previous month to €754 million a day, as higher crude oil prices and record seaborne oil earnings offset Western sanctions and kept Moscow's energy exports flowing.

China and India, the two largest buyers of Russian fossil fuels, recorded their highest monthly purchases since January 2022, highlighting Moscow's continued dependence on Asian markets even as Western governments tighten restrictions on its energy trade, the think tank said.

China purchased Russian fossil fuels worth €10.7 billion in October, while India's imports amounted to €6.4 billion. The European Union remained the third-largest buyer, with purchases of € 2.2 billion, followed by Turkiye at €1.1 billion and South Korea at €488 million.

YouTube Homework



महत्वपूर्ण तथ्य

Nvidia CEO Huang resigns as scandal raises security risks

Associated Press
HONG KONG

In a spectacular downfall for a vital player in the artificial intelligence boom, long-time head of U.S.-based chipmaker giant Nvidia, Jensen Huang, resigned as the company's CEO on Thursday after his extramarital affair raised national security concerns.

The company named Colette Kress, executive vice-president and chief financial officer, as its interim chief executive. The Board of directors also named Harvey C. Jones, an entrepreneur and venture investor, as its first-ever chairperson.

In a statement on Thursday, Ms. Kress said that Nvidia's "strength has always come from its people" and that she was "committed to building on the extraordinary foundation Jensen created over the last 33 years".

Mr. Huang faced growing calls to resign after his affair with a Chinese businesswoman, who reportedly was also acting as a spy for Beijing. China has denied that it engaged in any attempt to ensnare Mr. Huang.

Another affair

His troubles compounded on Wednesday after reports of another extramarital affair with an Nvidia employee who reported to him.

Shares of Nvidia tumbled 14% at the opening bell on Thursday, while the tech-heavy Nasdaq stock exchange slid 1.5%.

Nvidia's Board had gathered to discuss Mr. Huang's future after revelations about his affair with Alice Huang, a former executive at Singapore-based Megaspeed International.

The two persons are not related and details about Mr. Huang's affair with the former Megaspeed executive are unclear.



Jensen Huang

Megaspeed faced allegations last year that it was illicitly shipping advanced Nvidia computer chips into China, but in December said there was "no evidence" of such exports.

In its first statement since the scandal broke, Megaspeed said on Thursday that it takes its obligation to comply with U.S. export control laws "extremely seriously".

Megaspeed, which prominently touts a partnership with Nvidia on its website, said on Thursday that it has cooperated with the U.S. Department of Commerce's Bureau of Industry and Security (BIS), which handles enforcement of national security restrictions on technology exports, and was ready to "cooperate fully with any other relevant U.S. government authority".

Last month, the *Times* reported that U.S. intelligence agencies discovered that Mr. Huang had developed a close relationship with Alice Huang – and determined that she was feeding information directly to Beijing.

On Sunday, U.S. President Donald Trump said that the FBI was investigating.

Mr. Huang has lobbied Washington to loosen limits on sales of Nvidia chips to China. In January, he won Mr. Trump's approval to sell the company's H200 chips to China.

YouTube Homework

- Semiconductor बनाने वाले देशों का क्रम
- भारत कहाँ से Semiconductor का आयात करता है

महत्वपूर्ण तथ्य

India-Bangladesh consular dialogue postponed over rift

Kallol Bhattacherjee
NEW DELHI


Sheikh Hasina

Days after Bangladesh's deposed Prime Minister Sheikh Hasina requested Dhaka for a new passport and national identity card, the fifth India-Bangladesh consular dialogue scheduled for November 17 and 18 has been postponed, a diplomatic source has confirmed.

The source indicated that the postponement of the dialogue was mainly on account of growing tensions caused by Ms. Hasina's announcement that she will return to Bangladesh next month.

Last meeting in 2024

The planned consular dialogue would have been the first such meeting between the two sides in more than two years. The last such dialogue was held in New Delhi on May 29, 2024, just months before the Hasina government fell in a youth-led uprising in Dhaka.

The consular dialogue was scheduled to be held in Dhaka at the level of Directors-General of the Foreign Ministries of both countries.

The planned agenda included issues of border management, visa procedures, and the repatriation of citizens detained on both sides. The number of Indian visas issued was drastically reduced when tensions broke out in August 2024.

According to sources, India has gradually increased the number of visas issued to travellers from Bangladesh in recent months, especially after the election of Prime Minister Tarique Rahman in February this year.

Attempts at normalising the India-Bangladesh relationship in recent months have been hindered by Ms. Hasina's presence in India, where she took refuge on August 5, 2024. On November 9 this year, a London-based legal firm representing Ms. Hasina wrote to the High Commission of Bangladesh in New Delhi requesting a new passport and the national ID card.

Passport = Apply

5th India-Bangladesh Consular Dialogue — 17-18 Nov. 2024

YouTube Homework

↳ Bangladesh PM शेख हसीना → भारत में शरण ली → रद्द पासपोर्ट

महत्वपूर्ण तथ्य

'India-EU FTA can be a game changer'

German Ambassador terms deal a 'win-win' situation; he says German firms manufacturing in India can re-export to Europe, India's auto industry can become internationally more competitive through supply chain integration, and Tamil Nadu and other industrial hubs stand to benefit from the FTA

INTERVIEW

Jasper Wieck

Narayan Lakshman

In a wide-ranging interview, German Ambassador to India Jasper Wieck spoke to Narayan Lakshman about evolving European security architecture, the potential for growth in the India-EU FTA, bilateral clean energy and defence initiatives, and opportunities for skilled Indian workers in Germany.

The India-EU FTA negotiations concluded earlier this year. Which market access provisions would German manufacturers be looking for in areas like automobiles?

This agreement has the potential to become a game changer. We have a thriving trade and investment partnership already today.

Once German companies manufacture in India, they can better re-export to Germany and Europe as a whole, a market of 450 million people. That will be a huge momentum for (Indian) industry in terms of additional investments.

Regarding the potential sectors of investments, you have to consider the entire breadth of German industry and economy: engineering and machinery, automotive, pharmaceuticals and medical equipment, semiconductors, software, automation, defence and many more sectors. Our economy in Germany is very diversified, and they find the entire spectrum here as a potential market to make additional investments and increase trade.

If, e.g., the automotive sectors in Germany and India better integrate their supply chains, we can more easily procure production parts in India, and vice versa; your car industry can procure cheaper production parts and spare parts in Germany. Your automotive industry becomes internationally more competitive as it will be the case with ours. It is a win-win situation.

Are there areas where Germany and India can jointly deliver results on their climate commitments despite energy pressures?

Annually, we commit roughly €10 billion to support decarbonization worldwide, and India is a privileged partner in this endeavour. We have launched the Green and Sustainable Development Partnership four years ago, under which we offer technical support and loans amounting to more than €1 billion each year. These investments go into energy transition from fossil fuels to renewable energy, cleaner mobility and clean tech. This year we celebrate 20 years of Indo-German Energy Partnership, which shows that India and Germany have a long-standing tradition in this domain.

At the same time, I firmly believe that the most exciting chapter of this energy partnership is still ahead of us, because now it is about developing a renewable energy industry in India itself. In order to avoid replacing one dependency through another in buying solar panels or battery storages from other countries, you should rather produce them in India.



Where does Tamil Nadu fit for German supply chains that might move to India?

Tamil Nadu is already a primary destination for German investments. This has to do with the level of wages and energy prices, but also with a benign environment and incentives that the government of Tamil Nadu has put in place for foreign direct investments or joint ventures.

We have just been to Daimler Trucks, which has a huge plant producing trucks and buses not only for India, but also for Southeast Asia, Africa, and Latin America. They have decided to invest another ₹4,000 crore into their plant, also with a view to exporting to Europe in the future.

Are there more such projects from Germany being contemplated?

[A key] indicator is that we have high-level visits from various Länder of Germany. They always bring huge business delegations. We had Thüringen and Hessen; next week we will have Lower Saxony, a delegation of 60 people, most of them from business. That indicates a conjunction between the business that wants to get ready for the free trade agreement and the political side, which wants business to get ready.

Has the focus of German investors been mainly on industrial hubs such as the Chennai-Oragadam industrial belt, or does it expand beyond the metropolis to areas like Hosur, Coimbatore and tier two towns?

You mentioned two other important places where German companies have already invested and are keen to invest even more. In Coimbatore, it is automotive and clean-tech, wind energy. The company ZF provides equipment for wind energy power plants. In Hosur, it is two-wheelers, a joint venture between BMW with TVS.

Under Project 75(I), what would substantive technology transfer actually mean?

The final design of these submarines, which will be an Indian submarine, will be developed by both the Indian and the German shipyard together. It is not parachuted from Germany into India.

All six submarines will be produced in India, and the local content will increase over time, starting with 40% for the first submarine and then 60% or even more for the sixth submarine. Indian technology included in the construction will increase over time.

The German shipyard TKMS is ready to set up a production hub on the basis of the production of these six submarines for the Indian Navy, for the production of submarines for third markets: Southeast Asia or Latin America. Today most of the countries in Latin America are operating German submarines from the 1980s, so they have to have a new generation. Since our capacities for production in Germany are limited, it would be a win-win situation if this could also be done in India.

In addition, there are plans to develop together a heavy-weight torpedo. This would be a genuine Indo-German developed torpedo.

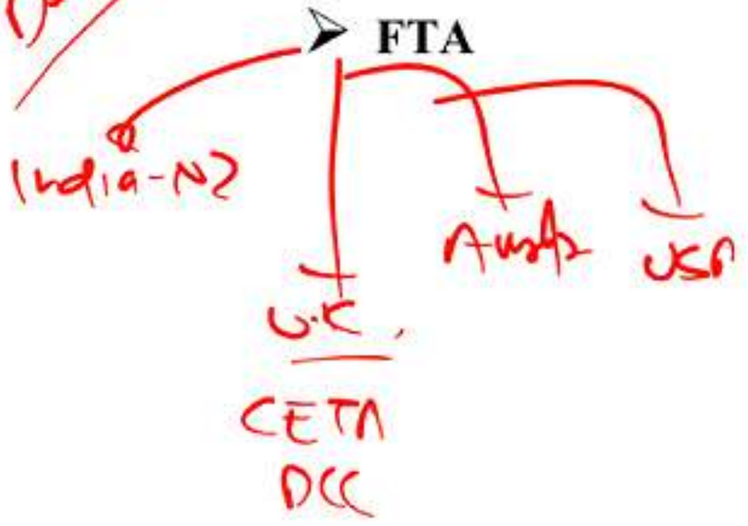
There are skilled Indians looking to migrate. Does Germany offer visas, schemes and initiatives for skilled Indians to move there and fill labour skill gaps in the German economy? What are their prospects? Do they get to stay on?

One very essential incentive is the studying opportunities at German universities. During my first stint, 17,000 Indian students were enrolled in German universities. Now we are at 70,000. Over a span of nine years, the number has increased fourfold. Once they have finished their studies in Germany, they are in a very good position to enter the German labour market. Roughly half of them stay in Germany.

For blue-collar jobs, German companies offer vocational training, which many Indians make use of. Here also, the numbers are going up steadily.

We issue 60,000 long-term visas each year, including those for students. I think we are now at 180,000 Indians who have come to Germany over the past years since the migration mobility agreement was signed in 2022. The numbers are going up, and there's huge satisfaction with these programmes.

YouTube Homework



महत्वपूर्ण तथ्य

No compromise with Ukraine, Putin indicates to U.S. envoys during talks

The Russian President proposes a short-term ceasefire in key frontline city in Donetsk; he also rules out agreeing to foreign troops being stationed in Ukraine; Kushner, Witkoff urge Putin to include European representatives in next round of talks

Agence France-Presse
MOSCOW

Vladimir Putin indicated on Thursday that Russia will not compromise on its hardline demands to end the Ukraine offensive, but offered a short-term ceasefire in a key frontline city in Donetsk during a Kremlin meeting with U.S. envoys.

The Russian President said he would not water down his territorial demands to control parts of Ukraine that Russia claims to have annexed, and ruled out agreeing to foreign peacekeeping troops being stationed in Ukraine – a deployment that he said would be a "continuation of war".

Jared Kushner and Steve Witkoff were in Moscow after two days of talks in Abu Dhabi searching for a way to end Europe's worst conflict since the Second World War.

Mr. Putin's comments appeared to douse hopes that a deal to end the war could be within grasp, after Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy said there was a "window of opportunity" to achieve "a result" before 2027.

The Americans, meanwhile, urged Mr. Putin to allow European representatives to sit at the table for the next round of talks.



Vladimir Putin speaks to U.S. envoys Steve Witkoff and Jared Kushner at the Senate Palace of the Kremlin on Thursday. AP

Moscow has successfully managed to reframe the discussions on the war as part of a wider discussion about European security.

But Kyiv and European leaders have urged against a new "Yalta" – a reference to the post-Second World War deal to carve the continent into spheres of influence – and said talks must be focused on ending the Ukraine war first.

Mr. Kushner and Mr. Witkoff will travel to Dublin, where a European summit is taking place, to meet Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy later on Thursday.

'No grey zones'

Usually held behind closed doors, the Kremlin chose to televise a lengthy opening exchange between Mr. Putin and the U.S. envoys.

The Russian leader also rejected talk of a possible territorial settlement involving "grey" – or demilitarised – zones between Ukrainian and Russian positions.

Russia-Ukraine Peace Talk 10-11 Nov 2026 कौन सी?

YouTube Homework

- Gaza Peace Plan – USA – 20 Point Gaza पर
- Mecca Pact – P|T|SA
- BADR Pact – P|T|I|Q

महत्वपूर्ण तथ्य

Taiwan 'reunification' must happen: Chinese President

Reuters
BEIJING

The tide of history cannot be stopped, Chinese President Xi Jinping said on Thursday, as he urged complete "reunification" of Taiwan with the motherland and pledged to do so peacefully, making no mention of the use of force.

China views democratically-governed Taiwan as its own territory, despite Taipei's strong rejection of that claim, and has repeatedly offered a "one country, two systems" model of autonomy not supported by any major Taiwanese political party.

Resolving the Taiwan question is an "unwavering historical mission" of China's Communist Party, Mr. Xi said in a speech in Beijing's Great Hall of the People.


Xi Jinping

"The tide of history cannot be stopped," Mr. Xi added. "The complete reunification of the motherland must be realised, and it will certainly be realised."

Mr. Xi's comments came in a speech on the 160th birthday of revolutionary hero Sun Yat-sen who helped lead a 1911 revolt that ended centuries of rule by emperors and empresses and ushered in the Republic of China.

Mr. Xi said China adheres to "peaceful reunification and the policy of 'one country, two systems'" and is willing to talk to Taiwan while upholding the "one China principle", or Beijing's position that both sides of the Taiwan Strait are one country.

All Chinese, including those in Taiwan, should join hands to jointly oppose Taiwan independence "separatist" forces and strive for peaceful development of cross-Strait ties, Mr. Xi added.

Despite Mr. Xi not mentioning the use of force, which China has never renounced for Taiwan, its military operates around the island on a daily basis, and is extending its reach further into the Pacific.

महत्वपूर्ण तथ्य

Yemen's Houthis say they targeted Saudi East-West pipeline

Houthi → SA

Agence France-Presse
RIYADH

Yemen's Houthis (Ansar Allah) said on Thursday that their forces targeted Saudi Arabia's East-West pipeline and an oil facility in the port city of Yanbu on the Red Sea.

The pipeline, which ends at Yanbu, has become increasingly important to the world's largest crude exporter, allowing it to get its oil to market after Iran blockaded the Strait of Hormuz at the outset of the West Asia war.

Houthi spokesperson Yahya Saree said in a post on X that one operation "targeted Pumping Station No. 7 on the East-West Pipeline using a drone", while a second "targeted the Yanbu oil facility using a ballistic missile".

He claimed both attacks – as well as two others targeting a Saudi airport and an airbase not far from the Yemeni border – had been successful.

The Houthis have repeatedly targeted the East-West pipeline, and on Monday Saudi Arabia said an attack on the conduit had sparked a fire but had not affected operations.

Mr. Saree also said the Houthis had attacked Saudi Aramco in Riyadh.

महत्वपूर्ण तथ्य

- सऊदी अरब की ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन (जिसे पेट्रोलाइन भी कहा जाता है) देश के पूर्वी हिस्से में स्थित अबकैक (Abqaiq) से शुरू होकर पश्चिमी तट पर लाल सागर (Red Sea) के किनारे बसे यानबू (Yanbu) शहर तक जाती है। लगभग 1,200 किलोमीटर लंबी यह पाइपलाइन अरब प्रायद्वीप के रेगिस्तानी इलाकों को पार करते हुए होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) का एक सुरक्षित विकल्प प्रदान करती है।

पाइपलाइन का मुख्य मार्ग (प्रांत और क्षेत्र)

- यह पाइपलाइन पूरी तरह सऊदी अरब की सीमा के भीतर तीन मुख्य प्रांतों से होकर गुजरती है:
- पूर्वी प्रांत (Eastern Province). सफर की शुरुआत अबकैक (Abqaiq) के विशाल तेल प्रसंस्करण केंद्र से होती है, जो फारस की खाड़ी के करीब स्थित है।
- रियाद प्रांत (Riyadh Province). यह पाइपलाइन देश के मध्य भाग यानी राजधानी रियाद के आसपास के इलाकों और पंपिंग स्टेशनों (जैसे अफीफ और दवाद्मी क्षेत्र) से होकर पश्चिम की ओर बढ़ती है।
- मदीना प्रांत (Medina Province). अंतिम चरण में यह हिजाज पर्वतमाला (Hijaz Mountains) और मदीना क्षेत्र को पार करते हुए लाल सागर के बंदरगाह तक पहुँचती है।

रास्ते में पड़ने वाले प्रमुख शहर और केंद्र

- यह पाइपलाइन घनी आबादी वाले शहरों के बीच से जाने के बजाय मुख्य रूप से रेगिस्तानी रास्तों और पंपिंग स्टेशनों से होकर गुजरती है, लेकिन इसके मार्ग में और आसपास कई महत्वपूर्ण शहर व औद्योगिक केंद्र आते हैं:
- अबकैक (Abqaiq). यह पाइपलाइन का शुरुआती बिंदु है, जहाँ सऊदी अरामको का सबसे बड़ा तेल प्रसंस्करण संयंत्र है।
- रियाद (Riyadh). देश की राजधानी रियाद इस मार्ग के मध्य क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख शहर है।
- अफीफ (Afif) और दवाद्मी (Dawadmi). रियाद और मदीना के बीच के इस रेगिस्तानी हिस्से में पाइपलाइन के कई महत्वपूर्ण बूस्टर पंपिंग स्टेशन स्थित हैं।
- मदीना (Medina). पश्चिमी हिस्से में यह पाइपलाइन पवित्र शहर मदीना के प्रांत से होकर गुजरती है।
- यानबू (Yanbu) और अल-मुअज्जिज (Al-Muajjiz). यह पाइपलाइन का अंतिम छोर है, जहाँ कच्चे तेल को रिफाइनरियों में भेजा जाता है या टैंकरों के जरिए यूरोप और अन्य देशों को निर्यात किया जाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

प्रधानमंत्री कार्यालय

Azadi Ka Amrit Mahotsav

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'किसान तक भारत कृषि सम्मेलन 2026' में भाग लिया

'विकसित भारत' के निर्माण के लिए कृषि विकास, स्मार्ट खेती और किसानों का सशक्तिकरण बहुत जरूरी है: प्रधानमंत्री

पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा क्रांति ने देश के 'अन्नदाताओं' को 'ऊर्जादाता' में बदल दिया है: प्रधानमंत्री

हम 'लैब टू लैंड' (प्रयोगशाला से खेत तक) की अवधारणा के साथ आगे बढ़ रहे हैं: प्रधानमंत्री

'नमो ड्रोन दीदियां' दिखा रही हैं कि गांवों में आधुनिक तकनीक का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जा सकता है: प्रधानमंत्री

भारत में एग्री-इंजीनियरिंग से लेकर एग्री-स्टार्टअप तक हर क्षेत्र में अवसर बढ़ रहे हैं। हमारा ध्यान किसानों को कृषि उद्यमी बनाने पर है: प्रधानमंत्री

प्रविष्टि तिथि: 12 NOV 2026 10:47PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज 'किसान तक भारत कृषि सम्मेलन 2026' में हिस्सा लिया। उन्होंने देश भर से आए कृषि वैज्ञानिकों, कृषि उद्यमियों और किसानों की उपस्थिति में सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अतीत में स्वच्छता अभियान में समूह की उत्साहपूर्ण भागीदारी और इस अनोखे 'किसान मेले' के आयोजन के लिए पूरे दो दिन समर्पित करने के लिए इस मीडिया समूह की सराहना की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मेलन दीपावली के कुछ ही दिनों बाद और छठ महापर्व के दौरान हो रहा है। यह ऐसा त्योहार है जो कृषि जीवन से गहराई से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि बिहू, पोंगल, ओणम, बैसाखी, सरहुल और पोला जैसे प्रमुख भारतीय त्योहार भी खेती-किसानी से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "इसका मतलब है कि कृषि और खेती हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारे सामाजिक जीवन का आधार हैं।"

महत्वपूर्ण तथ्य

जनजातीय कार्य मंत्रालय

15 November जन-15 नवंबर

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव 2026 का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में शुरू: "मौखिक परंपरा से समकालीन जनजातीय साहित्य तक"

"जनजातीय भाषाओं और मौखिक परंपराओं का संरक्षण विकसित भारत 2047 के निर्माण का एक महत्वपूर्ण आधार" – केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री

जनजातीय गौरव दिवस पखवाड़ा मनाने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा दो दिवसीय महोत्सव आयोजित

देशभर के जनजातीय लेखक, कवि, शोधकर्ता और भाषा विशेषज्ञ अपनी रचनाएं एवं विचार साझा करेंगे

पहले दिन के सत्रों में जनजातीय साहित्य, कवि सम्मेलन और जनजातीय लोककथाओं पर चर्चा; जीवंत जनजातीय मूल्यों, सांस्कृतिक विरासत के दस्तावेजीकरण में सामुदायिक सहमति, राज्यों के जनजातीय पोर्टलों को आपस में जोड़ने तथा अभिलेखीय संग्रहों के डिजिटलीकरण पर विशेष ध्यान केन्द्रित

माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवम्बर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया था। इसका उद्देश्य समृद्ध जनजातीय विरासत का उत्सव मनाना और जनजातीय नायकों के योगदान को राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा बनाना है। इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में दो दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया। जनजातीय गौरव दिवस पखवाड़े के अवसर पर आयोजित यह महोत्सव माननीय प्रधानमंत्री के प्रेरणादायी मार्गदर्शन में जनजातीय साहित्य, भाषाओं और मौखिक परंपराओं का उत्सव मना रहा है। इस महोत्सव में जनजातीय लेखक, कवि, शोधकर्ता और भाषा विशेषज्ञ एक मंच पर एकत्र हुए, जहां मौखिक परंपराओं से लेकर समकालीन साहित्य तक जनजातीय अभिव्यक्ति के विकास का उत्सव मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मंत्र "विरासत भी, विकास भी" के अनुरूप यह महोत्सव विकसित भारत 2047 की कल्पना की पुनः पुष्टि करता है, जो अपनी विरासत से शक्ति प्राप्त करता है और यह सुनिश्चित करता है कि जनजातीय भाषाओं एवं ज्ञान प्रणालियों का संरक्षण और संवर्धन हो तथा उन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल किया जाए।



इस महोत्सव का उद्घाटन माननीय केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम, माननीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके, नीति आयोग के माननीय सदस्य डॉ. जोराम अनिया, पद्मश्री श्री चामू कृष्ण शास्त्री, अध्यक्ष, भारतीय भाषा समिति, जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव श्रीमती रंजना चोपड़ा तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री अनंत प्रकाश पांडेय ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर देशभर के जनजातीय लेखक, शोधकर्ता और भाषा विशेषज्ञ उपस्थित थे।

महत्वपूर्ण तथ्य

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

Azadi Ka Amrit Mahotsav

57वां इफ्फी: 20 से 28 नवंबर 2026 तक गोवा में दुनिया भर के सिनेमा और रचनात्मक आवाज़ों का संगम

20-28 Nov

गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत शुरूआती प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, महोत्सव में 'स्टोरीज विदाउट बॉर्डर्स' की मुख्य झलकियां पेश की जाएंगी

57वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) 20 से 28 नवंबर 2026 तक गोवा में आयोजित होगा, जिसमें 'स्टोरीज विदाउट बॉर्डर्स' थीम पर सिनेमाई करिश्मों को लेकर दुनिया भर के फिल्म निर्माता, सिनेमा प्रेमी और रचनात्मक हस्तियां एक साथ जुटेंगी।

आगामी फेस्टिवल की मुख्य झलकियां, प्रमुख आकर्षण और अहम कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए कल, 13 नवंबर 2026 को गोवा के ताज सिडेड डी गोवा होराइजन में एक शुरूआती प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी।

इस कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत शामिल होंगे। इसके अलावा एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा (ईएसजी) की उपाध्यक्ष श्रीमती डेलिला लोबो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री चंचल कुमार, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनएफडीसी) के अध्यक्ष श्री जी. कृष्णकुमार, एनएफडीसी के प्रबंध निदेशक श्री धीरज सिंह, इफ्फी 2026 के फेस्टिवल डायरेक्टर श्री आशुतोष गोवारिकर और फेस्टिवल जूरी के अध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद रहेंगे।

इफ्फी की बढ़ती वैश्विक पहुंच को दर्शाते हुए, इसका 57वां संस्करण एक व्यापक और विविध कार्यक्रम पेश करेगा, जो भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा की समृद्धि का जश्न मनाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस महोत्सव के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी जाएगी और दुनिया भर से आने वाले दर्शकों व प्रतिभागियों के लिए नियोजित सिनेमाई अनुभवों और रचनात्मक आदान-प्रदान की एक झलक पेश की जाएगी।

स्टोरीज विदाउट बॉर्डर्स यानी सीमाओं के पार की कहानियां थीम के साथ, इफ्फी 2026 सिनेमा को एक ऐसे माध्यम के रूप में मनाना चाहता है, जो भौगोलिक और सांस्कृतिक सीमाओं से परे है, और जो विविध कहानियों तथा साझा मानवीय अनुभवों के जरिए दर्शकों को आपस में जोड़ता है।



Home Assignment

- ❑ World TB Day
- ❑ Smart City Mission



Thanks For Watching

Follow us for more Updates

@RRESULTMITRAOFFICIAL

Join our Telegram

@SUNILVERMA_THEIASMENTOR

Follow on Instagram

Subscribe Now

Stay Connected

Learn
Share
Grow
Together ♡

Better
Students
Brighter
Tomorrow

DISCIPLINE
CONSISTENCY
SUCCESS

Small
Steps
Big
Results